www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 185 || लखनऊ
मंगलवार
06 अक्टूबर 2026 || पृष्ठः 08 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://epaper.tamsasanket.com
दैनिक
तमसा संकेत
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
मौसम
सूर्योदयः 06:01
सूर्यास्तः 05:47
अधिकतमः 32°00
न्यूनतमः 23°00



पेज 07

विशेष समाचार | धर्म, अर्थ, 'काम', मोक्ष का... »पेज 04 | भाजपा ने रामप्रताप सिंह चौहान ... »पेज 06 | गोविंदा की बेटी टीना ने कोमल रानी पर ...

सीजेआई बोले- फॉर्म 6 में बदलाव को मंजूरी नहीं दी ■ ईसी ने कहा था- इजाजत मिली

'चुनाव आयोग ने कानून तोड़ा तो फैसले रोक देंगे'

इनकार

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े करीब 14 महत्वपूर्ण फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के निलंबन और SIR से जुड़े फैसलों को चुनौती देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि पहले संबंधित पक्षों का जवाब और रिकॉर्ड देखना जरूरी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR से संबंधित कई फैसले चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है और महत्वपूर्ण फैसले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिए जाने चाहिए। मामले में दायर याचिका के मुताबिक, SIR से संबंधित करीब 14 फैसलों को लेकर अन्य चुनाव आयुक्तों की ओर से आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इन्हीं आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक याचिका राकेश कुमार सिंह ने दायर की है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलीलें रखीं। इस याचिका में CEC को निलंबित करने समेत SIR से जुड़े फैसलों की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं। दूसरी याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई है। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी पेश हुईं।

>> (शेष पेज 06 पर)

> सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल एकतरफा कार्रवाई करने से इनकार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अंतरिम आदेश देना उचित नहीं होगा। यह भी संकेत दिया कि यदि रिकॉर्ड की जांच के बाद यह सामने आता है कि कोई फैसला आवश्यक सहमति या निर्धारित प्रक्रिया के बिना लिया गया था



ज्ञानेश कुमार पर एक्शन होगा या नहीं, 3 संभावनाएं

1. कार्यकाल के फैसलों पर पुलिस एक्शन नहीं हो सकता: ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 16 के तहत सुरक्षा मिली है। जब तक यह प्रावधान मौजूद है, उन्हें केवल पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी के जरिए हटाना, उन पर केस चलाना कानूनी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है।

2. भाजपा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया: ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक है, यानी अभी 2 साल कम से कम ज्ञानेश अपने पद पर रहेंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का मानना है कि ये आरोप आधारहीन हैं।

3. आखिरी रास्ता महाभियोग, लेकिन विपक्ष के पास बहुमत संभव नहीं: अनुच्छेद 324 (5) के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के तहत ही हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव को पेश करने के लिए लोकसभा में 100 तो राज्यसभा में 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति को यह तय करना होता है कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं। मौजूदा हालात में विपक्ष को महाभियोग प्रस्ताव को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 की जरूरत होगी। यानी लोकसभा में 362 सांसदों और राज्यसभा में 164 सांसदों का समर्थन हो। विपक्ष के पास संसद में इस वक्त इतना बड़ा समर्थन नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ ज्ञानेश कुमार पर विवाद

इस पूरे मामले की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें SIR को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच मतभेदों का जिक्र था। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने चुनाव पैनल के भीतर SIR प्रक्रिया को लेकर बार-बार चिंता जताई थी।

सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- फॉर्म -6 में किसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। जबकि, 9 दिन पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि एसआईआर के लिए फॉर्म -6 के साथ लगाए गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली है।

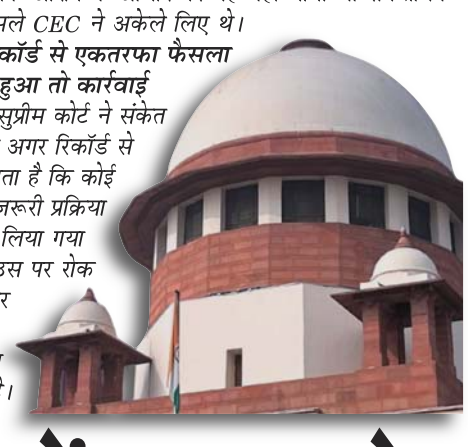
सुप्रीम कोर्ट की 4 बड़ी बातें: कार्रवाई के पहले जवाब जरूरी

1. अखबार की खबर के आधार पर आदेश नहीं दे सकते: *CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई खबर 100% सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। इसलिए सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर CEC को सस्पेंड करने का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। पहले चुनाव आयोग का जवाब और रिकॉर्ड देखना होगा।*

2. फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए: *सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से लिए जाने चाहिए। यानी तीन सदस्यीय आयोग में किसी एक सदस्य का अकेले फैसला पूरे आयोग का फैसला नहीं माना जा सकता।*

3. अभी यह नहीं मान सकते कि सारे फैसले CEC ने अकेले लिए: *सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले रिकॉर्ड देखना होगा। सिर्फ आरोप के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि सभी फैसले CEC ने अकेले लिए थे।*

4. रिकॉर्ड से एकतरफा फैसला साबित हुआ तो कार्रवाई संभव: *सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई फैसला जरूरी प्रक्रिया के बिना लिया गया था, तो उस पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता है।*



सीजेपी नेताओं का दावा : सरकार हमें अरेस्ट करने की तैयारी में

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया कि सरकार 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष, रत्ना और अन्य CJP नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने लिखा- अमित शाह आखिर कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे। प्रदर्शन में पूरा देश आ रहा है। सरकार को लगता है कि UAPA, NSA या जेल की सजा से हम डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो सालों तक जेल में भी रहेंगे। CJP ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में लेफ्ट, AAP और छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया।

बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम योगी

खाने का सामान बांटा, 40 हजार घरों में घुसा पानी

मुलाकात

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में बाढ़ प्रभावितों के बीच सोमवार को सीएम योगी पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों से हाल पूछा। खाने का सामान बांटा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों और नेपाल में भारी बारिश होने की वजह से वही पानी उतर रहा है। हम सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करने आए हैं। आप सभी के साथ डबल इंजन की सरकार खड़ी है। बता दें कि बीते 7 दिनों से गोमती का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रिवर फ्रंट, हनुमंत धाम, चंद्रिका देवी आदि तटीय मंदिर बाढ़ की चपेट में हैं। फैजुल्लागंज जैसे इलाके में बाढ़ के हालात हैं। 40 हजार घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। लोग पलायन कर रहे हैं। जहां पानी कम है, वहां कुछ लोगों ने सोमवार को नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। प्रभावितों से रिपोर्टर आशुतोष द्विवेदी ने बात की। एक ने कहा- राहत सामग्री अभी के लिए है।

>> (शेष पेज 06 पर)



अपराधियों में मौत का डर पैदा करना जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने रेप की 3 घटनाओं पर खुद नोटिस लिया

आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में नाबालिगों से गैंगरेप की 3 घटनाओं पर कहा, "जब तक अपराधी के मन में मौत का डर नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे।" सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि केवल चीजों को कागज पर लिखना पर्याप्त नहीं है, सख्त कार्रवाई करनी होगी। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सख्त होने से हिचकिचाएं नहीं। बेंच ने कहा कि कुछ लोग अनुच्छेद 21 यानी मानव अधिकार का हवाला देकर सवाल उठाएंगे, लेकिन पुलिस को अपना कर्तव्य निभाना होगा।

>> (शेष पेज 06 पर)





दिल्ली में हर दिन बच्चों से यौन अपराध के 4 मामले

NCRB के मुताबिक, 2024 में दिल्ली में POCSO के 1,553 केस दर्ज हुए। यानी औसतन हर दिन 4 से ज्यादा मामले सामने आए। 2025 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है।

फास्ट न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी लाइब्रेरी पर जवाब मांगा

नई दिल्ली। दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने सोमवार को केंद्र से जगह का लेआउट प्लान और पूरा ब्योरा हलफनामे में देने को कहा है।

19 विपक्षी दल कल दिल्ली में चुनाव आयोग घेरेंगे

नई दिल्ली। SIR को लेकर जारी विरोध के बीच 19 विपक्षी दल कल दिल्ली में चुनाव आयोग घेरेंगे। INDIA ब्लॉक के विपक्षी सांसद दिल्ली में 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' निकालेंगे। वे संसद से चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय तक करीब 3 किमी पैदल जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे नॉन-नेगोशिए-बल हैं। पहली- ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, दूसरी- SIR को रद्द करना। तीसरी- बैलट पेपर पर चुनाव कराना। देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और INDIA गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं।

मिजोरम में 5 करोड़ की हेरोइन जब्त

मिजोरम। मिजोरम में म्यांमार सीमा से होने वाली ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। असम राइफल्स ने 2 अक्टूबर को जोते इलाके में कार्रवाई करते हुए 2.5 किलो हेरोइन बरामद की। जब्त की गई हेरोइन की अनुमानित कीमत करीब 5.07 करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई के दौरान दो नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।

सोने की सिल्ली में ढलवाए जा रहे भ्रष्टाचार के पैसे

अखिलेश बोले- चढ़ावा चोरों की बातों पर किसी को भरोसा नहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वनस्पति राज में मंदिर में चोरी करवाने वाले उन भाजपाई चढ़ावा चोरों की झूठी बातों का भरोसा अब कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के चलते प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और चुनाव घोषित होते ही भाजपा हार जाएगी। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार के पैसों को सोने की सिल्ली में ढलवाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए, पूज्य शंकराचार्य तक पर प्रहार करवाए और भद्दे आरोप लगवाए, संविधान का विरोध करने के लिए बाबासाहेब की मूर्तियों तक को तुड़वा रहे हों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नाइंसाफी की हर हद पार कर गए हों और 'हाथरस की बेटी' के साथ अंतिम संस्कार तक का न्याय न किया हो, उनकी बातों पर अब भरोसा नहीं है।

>> (शेष पेज 06 पर)



यूपी में भाजपा के आठों राज्यसभा कैंडिडेट नए

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा के नाम नहीं, राज्यपाल गंगवार की बेटी को टिकट

ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार दोपहर 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सभी नए उम्मीदवार हैं। इनमें 2 महिलाएं हैं। इनमें 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 3 पिछड़े और 2 दलित हैं। पिछड़े वर्ग में एक लोधी, एक कुर्मी और एक पाल समाज से हैं। वहीं, दलित वर्ग में एक खटीक और एक पासी समाज से हैं। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया गया है। दिनेश शर्मा अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनाए गए हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)



लखनऊ से ज्यादा ताकतवर बना बाराबंकी

अवध का छोटा सा जिला बाराबंकी भाजपा की राजनीति में लखनऊ को छोड़कर अन्य किसी जिले अधिक ताकतवर हो गया है। भाजपा में प्रदेश महामंत्री उपेंद्र रावत बाराबंकी से हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैद्यनाथ रावत भी बाराबंकी से हैं। अब राज्यसभा चुनाव में भी बाराबंकी की प्रियंका रावत को टिकट दिया है। प्रियंका भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री सतीश शर्मा भी बाराबंकी जिले से ही हैं।

भाजपा ने खेला पिछड़ा कार्ड, ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश

भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछड़ा कार्ड खेला है। पिछड़े वर्ग में भी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक लोधी, पाल और कुर्मी समाज पर फोकस किया है। धर्मपाल सिंह लोधी समाज से हैं, प्रकाश पाल पाल समाज और श्रुति गंगवार कुर्मी समाज से हैं। वहीं, दलित वर्ग में भी 2017 से भाजपा का वोट बैंक माने जाने वाले पासी और खटीक समाज को ही मौका दिया है। विद्यासागर सोनकर खटीक समाज और प्रियंका रावत पासी समाज से हैं। राम प्रताप सिंह चौहान ठाकुर बिरादरी से हैं। जबकि राधाकांत ओझा और गोपी कृष्णा पांडेय ब्राह्मण हैं।

भाजपा ने UGC के नए नियमों से अगड़े वर्ग में पनपी नाराजगी और ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने के लिए ब्राह्मण समाज से दो प्रत्याशी बनाए हैं।

लेकिन ठाकुर समाज से एक प्रत्याशी कम कर दिया है। वर्तमान में नीरज शेखर और अरुण सिंह ठाकुर समाज से राज्यसभा सदस्य हैं। भाजपा ने दोनों को टिकट नहीं दिया है, लेकिन ठाकुर समाज से केवल एक राम प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है।

कार्यवाई : पूछा- मेरी मेडिकल रिपोर्ट शुभेंदु अधिकारी तक कैसे पहुंची, 2021 में व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार किया था

ममता का तीन अस्पतालों को कानूनी नोटिस

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। 2021 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पैर में फ्रैक्चर का दावा करने वाली ममता बनर्जी ने सोमवार को 3 अस्पतालों को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने पूछा है कि उनके इलाज से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी तक कैसे पहुंचे। यह मामला तब सामने आया है, जब शुभेंदु ने 3 अक्टूबर को आरोप लगाया कि ममता ने 2021 के चुनाव के दौरान अपनी चोट को लेकर गलत दावे किए थे। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच कराएंगे। दरअसल, 10 मार्च 2021 को नंदीग्राम में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ममता घायल हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया, जिससे कार का दरवाजा उनके पैर से टकराया और उनका पैर फैक्चर हो गया था। इसके बाद उनके पैर में प्लास्टर लगाया गया और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार किया था। कोलकाता के हाजरा चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान उनके सिर पर हमला हुआ; खोपड़ी में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट लगी, 18 टांके लगाए गए। राइटर्स बिल्डिंग मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में उन्हें चोट लगी और अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। सिंगूर-नंदीग्राम आंदोलन के दौरान कई मौकों पर उनके काफिले पर हमले हुए और रोकने की कोशिश हुई। इस दौरान चोट/हमले हुए थे।



ममता ने नोटिस में पूछा- मेरी सहमति क्यों नहीं ली गई

यह नोटिस 5 अक्टूबर को SSKM अस्पताल के निदेशक डॉ. मणिमय बंद्योपाध्याय, बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉ. पिजुश कुमार रॉय को और बांगुर इंस्टीट्यूट के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. अतनु विश्वास को भेजा गया है। ममता ने पूछा है कि मेडिकल रिकॉर्ड जारी करने से पहले उनकी सहमति ली गई थी या नहीं। क्या दस्तावेज जारी करने के लिए किसी अदालत ने आदेश दिया था। रिकॉर्ड का इस्तेमाल किसलिए हुआ। किन परिस्थितियों में इसे दिया गया। साथ ही, यह भी बताने को कहा गया है कि सार्वजनिक किए गए दस्तावेज मूल मेडिकल रिकॉर्ड थे या नहीं। इसकी एक कॉपी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजी गई है।



> अधिकारी ने कहा, "2021 में मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि उनका अपमान किया गया और उनका पैर टूट गया। हालांकि, उस समय बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज की रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं बताया गया था।"

सरकारी आश्रम स्कूल में 82 स्टूडेंट्स का आधा सिर मुंडवाया

बच्चों के खेलने से नाराज हो गए थे सुपरिटेंडेंट

तमसा संकेत, एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक सरकारी आश्रम स्कूल के 82 छात्रों को आधा गंजा कर देने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह घटना शनिवार को चिमूरा तालुका के जंभुलघाट स्थित सरकारी सेकेंडरी आश्रम स्कूल में हुई है। आश्रम से मिली जानकारी के मुताबिक, आश्रम में शनिवार सुबह को बच्चों के बाल काटे जा रहे थे। इसी दौरान कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों के इसी व्यवहार से सुपरिटेंडेंट प्रशांत मेश्राम नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में 82 बच्चों के आधे बाल कटवा दिए। रविवार के मामले का खुलासा हुआ तो अभिभावक भड़क उठे। स्कूल के प्रिंसिपल प्रशांत गिरी ने इस घटना को लेकर सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों के बाल काटने के लिए ट्रिमर का इस्तेमाल किया गया, जिससे उनके बाल टेढ़े-मेढ़े कट गए थे। छात्रों की अजीब और आधे-अधूरे तरीके से कटे बालों की तस्वीर शाम को वायरल हो गई थी।



> ट्रिमर का इस्तेमाल किया गया, जिससे बच्चों के बाल टेढ़े-मेढ़े कट गए थे।

भाजपा पर अखिलेश का हमला, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का लगाया आरोप

'जनता को अब भाजपाइयों पर भरोसा नहीं अन्याय'

कटाक्ष

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 'वनस्पति राज' में मंदिर में चोरी करवाने वाले भाजपा के 'चढ़ावा चोरों' की झूठी बातों पर अब जनता भरोसा नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। अपराध, अराजकता और बजट की लूट चरम पर है। अखिलेश यादव ने



सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये अपनी छवि चमकाने पर खर्च कर रही है, जबकि कमर तोड़ महंगाई के कारण खाना-पीना, दवाई-इलाज और पढ़ाई महंगी होती जा रही है। उन्होंने अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाए।

आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए और पूज्य शंकराचार्य पर प्रहार करवाने के साथ भद्दे आरोप लगवाए। उन्होंने कहा कि संविधान का विरोध करने वाले लोग बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्तियां तक तुड़वा रहे हैं। उनके मुताबिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अन्याय की हर हद पार की गई है और हाथरस की बेटी के मामले में अंतिम संस्कार तक न्याय नहीं मिला।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं,

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की प्रशासनिक अक्षमता का लाभ अधिकारी उठा रहे हैं। उनके मुताबिक कई मामलों में उनके अपने मंत्री तक न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए।

भर्ती और आरक्षण के मुद्दे पर भी हमला

सपा अध्यक्ष ने कहा कि नौकरी और भर्ती के मुद्दे पर युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने भर्ती मामलों के कोर्ट में फंसने, लेटरल एंट्री, संविदा और 'नॉट फाउंड सूटेबल' जैसे माध्यमों से आरक्षण का हक मारे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान और हुनरमंद लोगों के लिए यश भारती जैसे सम्मान और सम्मान राशि को बंद कर दिया गया। सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए।

किसानों और कारोबारियों के मुद्दे पर घेरा

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों को उनकी फसल और मेहनत का उचित दाम नहीं दिला पा रही है। किसानों को खाद, सिंचाई का पानी और बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने छुट्टा पशुओं की समस्या का भी जिक्र करते हुए सरकार पर किसानों की खेती की सुरक्षा न कर पाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के व्यापार और कारोबार को दूसरे राज्यों के ठेकेदारों के हाथों सौंपा जा रहा है। जीएसटी की मार से छोटे दुकानदार और कारखाने प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने हस्तकलाओं और शिल्पकारों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार की नीतियों से प्रदेश के स्थानीय उत्पादन को नुकसान पहुंच रहा है।

विरोधियों के फेक एनकाउंटर करवाए जाते हैं और बुलडोजर के जरिए लोगों के घर गिराए जाते हैं। अखिलेश ने कहा कि कॉरिडोर, पुल, एक्सप्रेस-वे और मंदिर के नाम पर पैसे खाने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि सत्ता से जुड़े लोगों को अपराध के बाद बचाया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा बढ़ी है। उन्होंने हिरासत में मौतों का रिकॉर्ड बनने का भी आरोप लगाया।

संवाद, संकल्प और सफलता के मूलमंत्र के साथ यूपी राइज का हुआ आयोजन

नवाचारियों ने एक्सपर्ट के सामने रखे नए आइडिया

तमसा संकेत, संवाददाता

झांसी। संवाद, संकल्प और सफलता के मूलमंत्र के साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में सोमवार को यूपी राइज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजन में नवाचारी युवाओं ने अपने स्टार्टअप आइडियाज को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ ही आसपास के कई जिलों से आए विद्यार्थियों एवं नवाचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर युवाओं और नवाचारियों को योगी सरकार की उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसके माध्यम से वे अपने स्टार्टअप के लिए आर्थिक मदद या व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त कर सकते है। कार्यक्रम स्थल पर इन योजनाओं में पंजीकरण कराने के लिए संबंधित विभागों की ओर से काउंटर लगाए गए। इस आयोजन में 12 स्टार्टअप्स की टीम ने अपने आइडियाज प्रस्तुत किए। इनमें से अभिषेक और निशांत के स्टार्टअप ऑन मिंट को विनर घोषित किया गया जबकि जबकि जुनैद रिजवान और सागर के स्टार्टअप इक्षू को रनर अवार्ड दिया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में स्टार्टअप फाउंडर, स्टूडेंट, विश्वविद्यालय के शिक्षक, स्टार्टअप मेंटोर, एक्सपर्ट उपस्थित रहे। नवाचारी युवाओं ने अपने आइडिया प्रस्तुत किए जिसे लेकर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए और योगी सरकार की योजनाओं के माध्यम से आर्थिक मदद प्राप्त करने के तरीके बताए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कवि मुकुल शर्मा ने युवाओं को अपनी रचनाएं सुनाकर युवाओं का मनोरंजन किया। मेंटोर एवं निर्णायक मंडल के तौर पर कनेक्स्ट मारकॉम के डायरेक्टर अलाय रिजवी, स्टूफिट के सीईओ डॉ सैयद शुजात हैदर जाफरी, इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉ नूर आलम खान उपस्थित रहे।

समाज के लोगों ने मंत्री से मूलभूत सुविधाओं की उठाई मांग

घुमंतू समाज के उत्थान और विकास के लिए समर्पित है राज्य सरकार
- असीम अरुण

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। लखनऊ कल्ली पश्चिम, लखनऊ में आयोजित 'घुमंतू समाज आभार सम्मेलन'(जनजाति बारा समाज सम्मेलन) में प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि हम यहाँ किसी चुनाव के सिलसिले में नहीं, बल्कि घुमंतू समाज के सर्वांगीण विकास और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने समाज को ''शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो'' के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मंत्री श्री असीम अरुण ने कहा कि आजादी की लड़ाई में इस समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतीत में हुए अत्याचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अब इस समाज पर कोई अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा।

'घुमंतू विकास मिशन एवं बोर्ड' सरकार द्वारा श्घुमंतू विकास मिशनश् और श्घुमंतू विकास बोर्डश् के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

क्षेत्र में सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, बारात घर, सामुदायिक भवन और सामुदायिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। समाज के लोगों के लिए शिविर लगाकर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवास योजना एवं रोजगार से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, फैजुल्लागंज से नैमिष तक नदी पर बनेगा तटबंध

स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नेक वेनम एंटी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फैजुल्लागंज से नैमिष तक हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की विभीषिका देखी, फिर बक्शी का तालाब क्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचकर उनका दुख-दर्द जाना और राहत सामग्री का वितरण किया। सीएम यहां स्वास्थ्य शिविर में भी पहुंचे और डॉक्टरों से दवाओं/ व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठे बाढ़ पीड़ित के पास पहुंचे और शासन से मिली राहत सामग्री, अन्न, चिकित्सा आदि सुविधाओं की हकीकत जानी। उन्होंने बच्चों को पास बुलाकर चॉकलेट भी दी।

मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में आई इस बाढ़ विभीषिका पर चिंता जताई। कहा कि गोमती नदी पर तटबंध बनने से काफी हद तक बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को फैजुल्लागंज से लेकर नैमिष तक नदी के तट का सर्वे कराते हुए तटबंध बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो गांव तटबंध के बाहर रहे, वहां बरसात का पानी निकालने की उचित व्यवस्था हो। तटबंध बनने के बाद नदी का जलस्तर बढ़े तो अंदर का पानी जमा होकर बीमारी न पैदा करे, बल्कि पंपिंग सेट लगाकर बाहर निकाला जाए।



स्कूल, मैरिज हॉल आदि में रुकने, भोजन आदि की व्यवस्था करे प्रशासन

सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से अपील की कि संकट की इस घड़ी में हम सभी मिलकर आपदा का सामना करें। गांव से बाहर आए लोगों के लिए खुले में सोने की बजाय स्कूल, मैरिज हॉल में व्यवस्था करें। वहां गर्म भोजन, बच्चों को दूध, गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार, पशुओं के चारे, भूसा-चोकर की व्यवस्था हो।

गांवों की सुरक्षा के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग, चौकीदार, होमगार्ड, पीआरडी जवान तैनात हो

स्कूल, मैरिज हॉल आदि में रुकने, भोजन आदि की व्यवस्था करे प्रशासनः मुख्यमंत्री



राजनाथ सिंह ने भी फोन कर जताई चिंता

सीएम ने आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फोन आने के बारे में बाढ़ पीड़ितों को अवगत कराया। बाढ़ को लेकर रक्षा मंत्री की चिंता के विषय में भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने फैजुल्लागंज से नैमिष तक तटबंध बनने से बाढ़ बचाव में मदद कराने के बारे में भी विमर्श किया। इस पर सीएम ने उन्हें बताया कि सरकार ने इसे स्वीकृत कर दिया है, धनराशि अवमुक्त करते हुए यह कार्य जल्द आगे बढ़ाएंगे। ऐसी पुख्ता व्यवस्था करेंगे तो हर सीजन में तटबंध उपयोगी होगा। बरसात में नदी का पानी उधर नहीं आएगा और इधर का पानी पंपिंग सेट के जरिए नदी की तरफ डाल दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि एलडीए ने ग्रीन कॉरिडोर बनवाया है, यह सड़क और सुरक्षा दोनों का काम कर रहा है। इसी तरह तटबंध पर चलने की भी व्यवस्था कराएंगे।

इकाना में वैभव सूर्यवंशी ने जमकर पसीना बहाया

लखनऊ । इकाना स्टेडियम में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने वेस्टइंडीज से भिड़ंत से एक दिन पहले जमकर पसीना बहाया। सोमवार को प्रैक्टिस करते हुए 1 घंटे में 15 छक्के मारे। इस दौरान 3 बार कैच भी उठा। बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्कल ने पेस बॉलर्स से वैभव सूर्यवंशी के लिए गेंदें डलवाईं। वैभव ने सबसे तेज शॉट्स मिडऑन और मिडऑफ पर लगाए।

सोमवार को भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीमों ने मीडिया से अपनी तैयारियों के बारे में बताया। भारतीय बॉलिंग कोच मोर्कल ने कहा कि हमारा फोकस कल का मैच जीतने पर रहेगा। युवा खिलाड़ियों पर नजरें हैं। वहीं, वेस्टइंडीज की तरफ से स्टार स्पिनर ने ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। जो बीत गया, वह अतीत था।

वेस्टइंडीज के अकील हुसैन को रिपोर्टर ने 100वें टी-20 इंटरनेशनल मैच के लिए बधाई दी गई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अभी 99 मैचों पर ही हैं।

34 हजार वालंटियर संभालेंगे दीप प्रज्वलन और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी

योगी सरकार के नेतृत्व में भव्य होगा 10वां दीपोत्सव

तमसा संकेत, संवाददाता

अयोध्या। दीपों की कतारें, रोशनी से जगमगाते मंदिर और सरयू तट पर आस्था का अद्भुत नजारा- अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वर्ष 10वां दीपोत्सव पांच से सात नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। राम की पैड़ी सहित करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में 33 लाख मिट्टी के दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आयोजन को भव्य और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपों की निर्बाध रोशनी के लिए 65 लाख बातियों और 55 हजार लीटर तेल की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन में इस्तेमाल होने वाली टी-शर्ट, मोमबत्ती, 150 किलो कपूर समेत अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर पांच टेंडर जारी किए गए हैं, जिनमें दीप-सामग्री, स्टेज निर्माण, सजावट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हैं।



इस बार दीपोत्सव को पहले से अधिक भव्य और व्यवस्थित बनाने के साथ सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में दीपों की पंक्तियों, फूलों की सजावट और प्रकाश व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं।



प्रमुख मंदिरों की एलईडी सजावट से निखरेगा अयोध्या धाम

34 हजार वालंटियर संभालेंगे दीपोत्सव की जिम्मेदारी

दीपोत्सव को सफल बनाने में इस बार 34 हजार वालंटियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये स्वयंसेवक दीप प्रज्वलन, व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखेंगे। आयोजन में शामिल होने वाले 34 हजार छात्रों के खान-पान की भी व्यवस्था की जा रही है। इससे युवा पीढ़ी को भी इस भव्य आयोजन से जुड़ने और दीपोत्सव का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा।

राम की पैड़ी से सरयू तट तक दिखेगी दीपों की भव्य छटा

श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद की ओर से इस बार भी दीपोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। राम की पैड़ी पर विशेष स्टेज तैयार किया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। दीपों से सजे घाट और रोशनी से नहाए प्रमुख मंदिर अयोध्या धाम की भव्यता को और बढ़ाएंगे। प्रमुख मंदिरों की एलईडी सजावट की तैयारियां भी आगे बढ़ रही हैं। सरयू तट से लेकर विभिन्न घाटों तक रोशनी की विशेष व्यवस्था की जाएगी। दीपों और रोशनी से सजी रामनगरी आस्था के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत और विकास की तस्वीर भी प्रस्तुत करेगी।

पीएम आवास योजना-शहरी में यूपी का देशभर में परचम

दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित

तमसा संकेत, संवाददाता

- **लाभार्थी आधारित आवास निर्माण में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक आवास पूर्ण कर यूपी ने हासिल किया प्रथम स्थान**
- **पीएमएवाई-यू 2.0 में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक ग्राउंडिंग के मामले में प्रदेश को मिला तीसरा स्थान**

लखनऊ। विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में देशभर में अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया। 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदेश को दो प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभार्थी केंद्रित व्यवस्था को मिली यह राष्ट्रीय मान्यता उत्तर प्रदेश की शहरी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (बीएलसी) घटक में उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत आवासों की कुल संख्या के सापेक्ष सर्वाधिक प्रतिशत आवासों की ग्राउंडिंग यानी धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कराने के मामले में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया है।

निर्देश : दवाओं की एमआरपी और खरीद कीमत में भारी अंतर पर एफएसडीए सख्त

अस्पताल फार्मेसियों में अब मरीज जान सकेंगे दवा की खरीद और बिक्री कीमत

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। दवाओं की खरीद कीमत और मरीजों को बेचे जाने वाले मूल्य के बीच बड़े अंतर तथा अस्पताल फार्मेसियों में कीमत संबंधी जानकारी की पारदर्शिता की कमी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश (यूपीएफएसडीए) ने महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने प्रदेश की सभी रिटेल फार्मेसियों को अपनी पब्लिक वेबसाइट स्थापित कर उस पर फार्मेसी, लाइसेंस, फार्मासिस्ट और स्टॉक से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, अस्पताल परिसर में संचालित अथवा इन-पेशेंट मरीजों के लिए संचालित ऐसी फार्मेसियों, जहां मरीजों के पास दवा, मेडिकल डिवाइस या न्यूट्रास्युटिकल्स खरीदने का व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर दवाओं की प्राइस टू रिटेल (पीटीआर) और प्राइस टू कंज्यूमर (पीटीसी) संबंधी जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था मूल्य नियंत्रण का आदेश नहीं, बल्कि जनहित में फार्मेसियों द्वारा आवश्यक जानकारी के सेल्फ-डिस्क्लोजर पर आधारित पहल है। ड्रग सेफ्टी, जनहित में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की निर्बाध आपूर्ति की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण पहल है। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान विभाग के संज्ञान में आया कि औषधि निर्माता, मार्केटिंग फर्म और स्टॉकिस्ट कई अस्पताल स्थित फार्मेसियों को एमआरपी की तुलना में काफी कम दरों पर भारी छूट के साथ दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। विभाग के आदेश के अनुसार कई मामलों में दवाओं की एमआरपी उनके खरीद मूल्य से कई गुना अधिक पाई गई।

जनहित में
यूपीएफएसडीए का बड़ा कदम, अस्पतालों और रिटेल फार्मेसियों को पब्लिक वेबसाइट बनाने का निर्देश, क्यूआर कोड से भी मिलेगी जानकारी
अस्पताल फार्मेसियों को वेबसाइट पर पीटीआर और पीटीसी बताना होगा, सभी फार्मेसियों को लाइसेंस, फार्मासिस्ट और साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश

डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर

कमिश्नर, एफएसडीए डॉ. रोशन जैकब ने अपने आदेश में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ)-2013 के प्रस्तर 25 का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रत्येक रिटेलर और डीलर को निर्माता अथवा आयातक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल्य सूची को अपनी दुकान या कारोबार की जगह पर ऐसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होता है, जहां इच्छुक व्यक्ति उसे आसानी से देख सके। यूपीएफएसडीए के अनुसार डीपीसीओ का यह प्रावधान अस्पताल फार्मेसियों सहित सभी फार्मेसियों पर लागू है। हाल के महीनों में विभाग की ओर से की गई प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान सामने आए तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ कि कई लाइसेंसी फर्मों द्वारा इस प्रावधान के अनुरूप अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR-D), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रायोजन में Best Practices in Prison Administration विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज कारागार मुख्यालय, लखनऊ में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश श्री पी.सी. मीना रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी अपर महानिरीक्षक कारागार (प्रशिक्षण), डॉ रामधनी द्वारा महानिदेशक कारागार को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रभारी अपर महानिरीक्षक कारागार (प्रशि./वि.) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विषय विशेषज्ञों एवं विभागीय प्रवक्ताओं द्वारा कारागार प्रशासन की बेहतर कार्यप्रणालियों, नए प्रयोगों और सुधारात्मक प्रयासों पर व्याख्यान दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न राज्यों में किए जा रहे अच्छे कार्यों और उनके अनुभवों को भी साझा किया जाएगा। अपने संबोधन में महानिदेशक कारागार श्री पी.सी. मीना ने कहा कि कारागार प्रशासन में सुरक्षा के साथ-साथ सुधार और पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में किए जा रहे अच्छे कार्यों और सफल प्रयोगों से सीखने तथा उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा के कारागार अधिकारी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश के अलावा तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कारागार प्रशासन के क्षेत्र में अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों और नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

50 दिन से तेंदुए की दहशत, ग्रामीणों में फैली दहशत, 18 सेकंड का वीडियो

बाराबंकी में खेतों में घूमता दिखा तेंदुआ

हड़कंप

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। हैदरगढ़ क्षेत्र की ग्रामसभा शरीफाबाद में सोमवार सुबह खेतों के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने तेंदुए को चहलकदमी करते देखा। इस दौरान उसका करीब 18 सेकंड का वीडियो भी बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीण रामजीत कश्यप ने बताया कि सोमवार सुबह वह खेत में तुलसी काट रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर तेंदुए पर पड़ी। तेंदुए को देखते ही उन्होंने आसपास के लोगों को



जानकारी दी और ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिनों से इलाके में तेंदुए की मौजूदगी के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

वन विभाग की टीम कर रही जांच

वन दरोगा अनुज सिंह ने बताया कि शरीफाबाद में तेंदुआ दिखाई देने की जानकारी सही है।

वन विभाग की टीम मौके पर मामले की जांच कर रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

तेंदुए की लगातार मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों में खेतों और आसपास के इलाकों में जाने को लेकर भय बना हुआ है। ग्रामीण वन विभाग से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।



सोमवार सुबह दोबारा खेतों में तेंदुआ दिखाई देने के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई।

50 दिन से तेंदुए की हलचल से ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों के मुताबिक, शरीफाबाद गांव और आसपास के इलाके में पिछले 50 दिनों से अधिक समय से तेंदुए की हलचल बनी हुई है। इससे ग्रामीणों में पहले से ही डर का माहौल है। बताया गया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से गांव में पिंजरा भी लगाया गया था। ग्रामीणों का दावा है कि तेंदुआ अब तक कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका है।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप

परिजनों ने एसपी से की शिकायत, समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

रायबरेली। रायबरेली में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में हरचंदपुर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और बेटी का दोबारा मेडिकल कराने की मांग की है। यह मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़ीखास गांव का है। पीड़ित छविनाथ लोध ने बताया कि 2 अक्टूबर को उनकी नाबालिग बेटी शौच के लिए गई थी। आरोप है कि अमन पासी और नीरज पासी उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बेटी के थाने पहुंचने पर पिता ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने 1 लाख रुपये लेकर समझौता करने का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। उनसे सादे कागजों पर जबरन दस्तखत भी कराए गए। ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत समेत कुछ



लोगों पर फोन से धमकी देने और मामले को दबाने का आरोप है। पीड़ित के पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। बेटी के डरे होने के कारण दोबारा मेडिकल जांच की मांग की गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बेटी के थाने पहुंचने पर पिता ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने 1 लाख रुपये लेकर समझौता करने का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। उनसे सादे कागजों पर जबरन दस्तखत भी कराए गए। ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत समेत कुछ लोगों पर फोन से धमकी देने और मामले को दबाने का आरोप है।

फास्ट न्यूज

उन्नाव में लोडर की टक्कर से किशोरी की मौत

उन्नाव। उन्नाव के गंगाघाट इलाके में सोमवार सुबह राजधानी मार्ग पर वी-मार्ट के पास तेज रफ्तार लोडर ने मां-बेटी को टक्कर मार दी। हादसे में बीए की छात्रा विविध भारती की मौत हो गई, जबकि उसकी मां मंजू गंभीर रूप से घायल हो गईं। विविध भारती अपनी मां मंजू के साथ शुक्लागंज में डॉक्टर अनुज तिवारी से दवा लेने आई थीं।

कलेक्ट्रेट में युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश

उन्नाव। उन्नाव में जमीन से जुड़े विवाद में अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया और आग लगाने से रोक दिया। इसके बाद अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार ने उसकी समस्या सुनी और समाधान का भरोसा देकर उसे शांत कराया। माखी थाना क्षेत्र के अकबरपुर दबौली गांव निवासी मोहन द्विवेदी सोमवार दोपहर करीब एक बजे कलेक्ट्रेट पहुंचा था। वह जमीन से संबंधित अपनी शिकायत अधिकारियों के सामने रखना चाहता था।

खाना खाते समय गिरी घर की दीवार

हरदोई। हरदोई में घर के अंदर बैठकर भोजन कर रही एक बुजुर्ग महिला अचानक भरभराकर गिरी दीवार के मलबे में दब गई। परिजन आनन-फानन में उन्हें मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने रविवार की शाम करीब 6 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोमवार की दोपहर 2 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामला बघौली थाना क्षेत्र के ककरहिया गांव का है।

सेवा संकल्प शिविर में 198-लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

बाराबंकी में राज्यमंत्री ने बांटे स्वीकृति प्रमाण पत्र और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बाराबंकी के रामसनेही-घाट मिनी स्टेडियम में सोमवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया। इसमें 198 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी बांटे गए।

राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। शिविर में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से 103 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और 25 को बैसाखी के जोड़े दिए गए।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने



शादी अनुदान योजना के 20 और छात्रवृत्ति योजना के 10 लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए।

समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के 10-10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और निराश्रित महिला पेंशन योजना के क्रमशः पांच, पांच और 10 लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिए गए।

बस की टक्कर से महिला की मौत

पति की हालत गंभीर, बहनोई के घर नामकरण की दावत में जा रही थी

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। लोनार कोतवाली क्षेत्र में रविवार को हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। फर्रुखाबाद से हरदोई के सरैंया गांव नामकरण संस्कार में शामिल होने आ रही महिला की बाइक में पीछे से तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोट आई। मेडिकल कॉलेज से लखनऊ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। हादसे में महिला के पति को भी मामूली चोटें आई हैं। घटना लोनार कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर के पास की है।

फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी राकेश सिंह अपनी पत्नी अनीता सिंह (28) के साथ बाइक से हरदोई के सरैंया गांव जा रहे थे। सरैंया निवासी उनके साढ़ू शेखर के घर बेटे का नामकरण



संस्कार था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दोनों घर से निकले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल अनीता को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर लखनऊ जा रहे थे, तभी रविवार की देर शाम करीब सात बजे रास्ते में उनकी मौत हो गई।

पति को मामूली चोट, परिवार में मचा कोहराम

हादसे में अनीता के पति राकेश सिंह को भी चोटें आईं, हालांकि उनकी हालत सामान्य बताई गई। अनीता की अचानक मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। नामकरण संस्कार की खुशियां मातम में बदल गईं। मृतका अपने पीछे दो बेटों और एक बेटी को छोड़ गई हैं। सोमवार दोपहर करीब एक बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

पीछे से रोडवेज बस ने मारी टक्कर

जगदीशपुर के पास पहुंचने पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अनीता बाइक से नीचे गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल अनीता को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर लखनऊ जा रहे थे, तभी रविवार की देर शाम करीब सात बजे रास्ते में उनकी मौत हो गई।

सांसद ने मतदान जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी

उन्नाव में 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' कार्यक्रम, जनभागीदारी का आह्वान

- रैली के जरिए लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक मतदान करने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
- रंगोली के माध्यम से सेवा, राष्ट्रहित और संकल्प का संदेश दिया गया।

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में जीआईसी ग्राउंड में सोमवार दोपहर 12 बजे 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' आभार एवं संकल्प की रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन्नाव सांसद डॉ. स्वामी



सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज और भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने मतदान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए लोगों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिक से अधिक मतदान करने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजकों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतदान अधिकार के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सेवा, राष्ट्रहित और जनभागीदारी के महत्व पर विचार रखे। युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को विशेष रूप से अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने लोगों से आगामी चुनाव में बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की। रंगोली के माध्यम से सेवा, राष्ट्रहित और संकल्प का संदेश दिया गया। उपस्थित लोगों ने देशहित में कार्य करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लिया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मतदाताओं से बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपने विवेक के आधार पर मतदान करने की अपील की।

10 लाख बीमा और कैशलेस इलाज की भी मांग, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

समूह सखियों ने 20 हजार मानदेय मांगा

तमसा संकेत, एजेंसी

हरदोई। हरदोई जनपद के अलग-अलग ब्लॉकों से पहुंचीं सैकड़ों समूह सखियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी एकता का कड़ा संदेश दिया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। यह प्रदर्शन सोमवार की दोपहर 1:45 बजे किया गया। प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने डीएम को संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार को सौंपा। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों के गठन से लेकर उनके संचालन तक की अहम जिम्मेदारी समूह सखियां निभाती हैं,



लेकिन इसके एवज में मिलने वाला मात्र दो हजार रुपये का मानदेय आज के इस महंगाई के दौर में भरण-पोषण, मोबाइल रिचार्ज और आने-जाने के भाड़े के लिए बेहद नाकाफी साबित हो रहा है। समूह सखियों ने अपनी प्रमुख मांगों के तहत मानदेय बढ़ाकर बीस हजार रुपये प्रतिमाह करने और प्रत्येक सखी को दस लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा पांच लाख रुपये तक की



- मानदेय बढ़ाकर बीस हजार रुपये प्रतिमाह करने और प्रत्येक सखी को दस लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की पुरजोर मांग उठाई।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की पुरजोर मांग उठाई। इसके अलावा कार्य के लिए इंटरनेट रिचार्ज सहित टैबलेट या मोबाइल उपलब्ध कराने, मानदेय ग्राम संगठन के बजाय सीधे निजी खातों में भेजने, सभी को स्थायी करने के साथ ड्रेस व आईडी प्रूफ देने तथा छह माह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई। कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपने के बाद सभी महिलाएं कतारों में अंबेडकर पार्क पहुंचीं। जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर एक बैठक की और आगे की रणनीति पर गहन मंथन किया।

निर्देश : उन्नाव सांसद बोले- अखिलेश की नजर हमारे वोट बैंक पर, भाजपा में उचित सम्मान की पैरवी करूंगा

लोधी समाज खिसका तो सरकार बनाना मुश्किल : साक्षी महाराज

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज सोमवार सुबह करीब 9 बजे अपने संसदीय कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जनता दर्शन कर लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव, लोधी समाज, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, चुनाव आयोग और विपक्ष को लेकर कई बयान दिए। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के 'लोधी बनाम योगी' के बयान पर कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने चार दिन पहले



कहा था कि चुनाव 'देश बनाम योगी' होगा। अब 'लोधी बनाम योगी' की बात कही जा रही है। उन्होंने इसे अखिलेश यादव की चुनाव से पहले हार स्वीकार करने जैसा बताया। सांसद ने कहा कि लोधी समाज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, रानी अवंतीबाई और अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी से जुड़ा समाज है और राष्ट्रवाद के सिद्धांत को नहीं छोड़ सकता। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष के सवालों को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि पहले चुनाव में वोटों की चोरी और मतपेटियां लूटने जैसी घटनाएं होती थीं, लेकिन अब चुनाव व्यवस्था अधिक पारदर्शी है।

सांसद ने कहा - यदि चुनाव व्यवस्था पारदर्शी नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटें नहीं जीतती। उन्होंने कहा कि भाजपा को 33 सीटें मिलीं और सपा को 37, इसलिए विपक्ष को निर्वाचन आयोग की व्यवस्था पर सवाल उठाने के बजाय उसकी पारदर्शिता की सराहना करनी चाहिए।

लोधी समाज को सम्मानजनक साझेदारी जरूरी

साक्षी महाराज ने कहा कि भाजपा को लोधी समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वह प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोधी समाज खिसक गया तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। सत्ता और संगठन में समाज को सम्मानजनक साझेदारी देना जरूरी ही नहीं, बल्कि अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोधी समाज को अधिक टिकट देने की बात कर रहे हैं तो यह उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास है। साक्षी महाराज ने दावा किया कि यदि जरूरत पड़ी तो वह भाजपा में लोधी समाज को बड़ी संख्या में टिकट देने की पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है।

उन्नाव के लोगों का सहयोग कभी नहीं भूलूंगा

सांसद ने कहा कि वह सात बार सांसद बन चुके हैं और भाजपा ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने उन्नाव की जनता का भी आभार जताते हुए कहा कि एक क्षेत्र से लगातार तीन बार सांसद चुना जाना और बड़ी संख्या में वोट हासिल करना सामान्य बात नहीं है। उन्नाव के सभी वर्गों के लोगों ने जो सहयोग दिया, उसे वह जीवनभर नहीं भूलेंगे।

धीरेंद्र प्रताप हत्याकांड : सीबीआई जांच की मांग पर हुआ प्रदर्शन

एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, परिजन बोले- मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी हो

- धीरेंद्र प्रताप हत्याकांड के विरोध में ग्रामीण लखनऊ जाने के लिए निकले। एसडीएम ने उन्हें समझाया।
- 1000 से ज्यादा ग्रामीणों की भीड़ सड़क पर उतरी तो अफसर मौके पर पहुंचे।

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के राजेपुर गांव निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह की 31 अगस्त को हुई हत्या के मामले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे ग्रामीणों और परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। करीब एक हजार ग्रामीण मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने के लिए लखनऊ कूच कर



रहे थे। इसकी जानकारी पर बांगरमऊ एसडीएम ब्रज मोहन शुक्ला मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। मृतक के भाई अवधेश प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि घटना में स्थानीय पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। उन्होंने हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की। परिजनों ने कहा कि जब तक हत्या की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, उन्हें न्याय मिलने का भरोसा नहीं है। ग्रामीणों के लखनऊ कूच की सूचना पर एसडीएम ब्रज मोहन शुक्ला करीब दो किलोमीटर दूर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राजेपुर ग्राम सभा के धीरेंद्र सिंह की करीब एक माह पहले हत्या हुई थी। परिजन और ग्रामीण हत्या के खुलासे के लिए सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए थे। एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर उसे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी मांगों पर सात दिन में उचित कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ग्रामीण शांतिपूर्वक लौट गए। पुलिस के अनुसार मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है।

सम्पादकीय

हताशा भरा अभियान



अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर जैसा अभियान छेड़ दिया है, उसका प्रतिवाद करने के लिए दोनों चुनाव आयुक्तों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि वे उसी संवैधानिक संस्था के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए, क्योंकि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का हर पहलू उसकी जानकारी में है और उसने इस प्रक्रिया को बार-बार अपनी सहमति भी प्रदान की है। यदि उसने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो कल को उसके साथ-साथ अन्य संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा सकता है।

लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से ही शक्ति पाता है। उन्हें कमजोर करने का अर्थ है लोकतंत्र को खोखला करना। अभी तक विपक्ष यह काम केवल निराधार आरोपों और एसआइआर प्रक्रिया की छोटी-मोटी त्रुटियों को तिल का ताड़ बनाकर कर रहा था, लेकिन अब उसकी ओर से शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में अराजकता का सहारा लेने की भी कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ जनता को गुमराह करने वाले भड़काऊ नारे कोई शुभ संकेत नहीं।

अब इसमें भी कोई संदेह नहीं कि काकरोच जनता पार्टी का भी एजेंडा वही है, जो हताश-निराश विपक्ष का है। विपक्षी दल इसलिए आपे से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि एसआइआर के खिलाफ उनकी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टिक नहीं पा रही हैं। केरलम सरकार की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बीस वर्ष पुराने मामले को खोलना केवल कांग्रेस की हताशा का ही परिचायक नहीं, बल्कि इसका भी सूचक है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है।

विपक्षी दल इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति को लेकर जो नैरेटिव खड़ा किया गया था, वह भोथरा पड़ चुका है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि जिस चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार कर विश्व में अपनी एक साख बनाई है और भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उसे विपक्षी राजनीतिक दल मनगढ़ंत आरोपों के सहारे धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

हर कोई इससे अवगत है कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर अशुद्धियां हैं और उन्हें ठीक करने का काम एसआईआर के जरिये ही हो सकता है, लेकिन इस झूठे आरोप के सहारे उसका विरोध किया जा रहा है कि इससे राजनीतिक दल विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। यदि वास्तव में ऐसा है तो कांग्रेस केरलम में सत्ता में कैसे आ गई और तमिलनाडु में भी विपक्षी दल ने जीत कैसे हासिल कर ली?

अधिकार और जिम्मेदारी

युग बीत गए मगर अधिकार और कर्तव्य के बीच की जंग जारी है। यह बताना तो जरा मुश्किल है की जंग मे कौन किस पर भारी है। कुएं के पानी पर हमारा अधिकार है पर उसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी हैं । वह अगर हम ऐसा नहीं कर रहें हैं तो समझ लो विनाश की पूरी तैयारी है। वह जो केवल अधिकारों के लिए अपने पूरे जीवन को खपा देते है वे वसीयत मे कंगाली के काले दस्तावेज नई पीढी के हिस्से मे छोड जाते है। हमारी आने वाली पीढियां भी हमे याद करें,हमारे त्याग का सम्मान करें तो हमें भी कर्तव्यों को निभाना है ऐसा हमारे बुजुर्ग हमे समझाते हैं। आज हमारे समाज में एक मौन संघर्ष चल रहा हैं । अधिकार और जिम्मेदारी के बीच हैं । सरकार ने समानता के सिद्धांत पर चलते हुए बेटा और बेटी दोनों को माता- पिता की संपत्ति का समान हिस्सेदार घोषित किया हैं । यह कदम निश्चय ही महिलाओं के अधिकार और सम्मान की दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं। यह कदम बराबरी की दिशा में हैं लेकिन इसी बराबरी के बीच एक मौन असंतुलन छिपा हुआ हैं । एक गंभीर प्रश्न यह भी उठता हैं कि क्या केवल अधिकार ही समान होने चाहिए या फिर जिम्मेदारियां भी ? अधिकार पाने की इच्छा कोई जागरूकता की श्रेणी में नहीं आता है, फिर अधिकार के नाम की पिपासा में कोई क्यों भटकता जाता है । कर्तव्य व दायित्व का बोध हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, उस मार्ग पर निरन्तर गतिमान होने वाले ही का जीवन हर पल संवरता है । अधिकार के दावे को छोड़ो व कर्तव्य के पथ पर उत्साह से प्रस्थान करते रहो, जीवन के हर पल हर क्षण को कर्तव्य व दायित्व पालन की अमूल्य संपदा से सदा भरते रहो । जिम्मेवारी निभाने वाले को सच्ची लगन और श्रद्धा निष्ठा का बोझ भी उठाने लायक होना होता है ।हर कोई हर तरह की जिम्मेवारी उठा पाएं ,ये सम्भव भी कम होता है । सबको अपनी योग्यतानुसार जिम्मेदारियों का बोझ सक्षम हाथों में सौंपा जाए , जो सब तरह के समझ अनुरूप उस को अच्छे से संभाल पाएं , यह बहुत आवश्यक होता है।

› प्रदीप छाजेड़

धर्म, अर्थ, 'काम', मोक्ष का संगम हैं रामलीलाएं

> 66 रामलीला का कोई एक अखिल भारतीय प्रारूप नहीं है। उत्तर भारत में इसकी अनेक शैलियां विकसित हुईं। कहीं संवाद और गायन प्रधान है, कहीं झांकियां महत्वपूर्ण हैं, कहीं पूरा नगर ही रामलीला का मंच बन जाता है।



रामलीलाएं केवल रामकथा का मंचन नहीं , भारतीय समाज की धार्मिक आस्था, लोककला, अभिनय, संगीत, संवाद, सामाजिक सहभागिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था का ऐसा संगम है, जिसमें सदियों की सांस्कृतिक यात्रा दिखाई देती है।

रामकथा की भारत में अत्यंत प्राचीन परंपरा है। वाल्मीकि रामायण से लेकर विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचे गए रामकाव्यों ने इस कथा को जन-जन तक पहुंचाया। मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस ने रामकथा को लोकभाषा और लोकजीवन से गहरे जोड़ने का काम किया। माना जाता है कि तुलसीदास से जुड़ी रामकथा की लोकमंचीय परंपराओं ने आगे चलकर रामलीला के विभिन्न रूपों को व्यापक आधार दिया।

वाराणसी की रामनगर रामलीला इसका विशिष्ट उदाहरण है, जहां रामकथा का मंचन एक दिन या एक मंच तक सीमित न रहकर कई दिनों तक विभिन्न स्थानों पर चलता है।

यही विविधता रामलीला को केवल धार्मिक आयोजन न रहकर लोकसंस्कृति का जीवंत दस्तावेज बनाती है।

धार्मिक आयाम:

रामलीला का मूल आधार आस्था है। राम मर्यादा के प्रतीक हैं, सीता त्याग और धैर्य की, लक्ष्मण कर्तव्य की, भरत भ्रातृप्रेम की और हनुमान समर्पण तथा सेवा की। रामलीला का धार्मिक महत्व इस बात में है कि यह मंदिर की चारदीवारी से बाहर आकर धर्म को सार्वजनिक जीवन से जोड़ती है। हजारों लोग एक साथ कथा सुनते और देखते हैं। पूजा और मनोरंजन के बीच की दूरी यहां बहुत कम हो जाती है लेकिन रामलीला की सार्थकता केवल धार्मिक भाव-विभोरता में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जिन्हें रामकथा समाज के सामने रखती है। यदि रामलीला देखकर मनुष्य सत्य, संयम, करुणा, कर्तव्य और न्याय के प्रश्नों पर विचार करे तो उसकी धार्मिकता कर्म में बदलती है।

कला और कर्म की पाठशाला

रामलीला भारतीय लोककला की बड़ी पाठशाला है। अभिनय, संवाद, गायन, वादन, वेशभूषा, मुखौटे, मुकुट, आभूषण, मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और चित्रकला - कला की कितनी ही विधाएं इसमें एक साथ समाहित हैं।

एक रामलीला के पीछे केवल अभिनेता नहीं दर्जी, बढ़ई, रंगकर्मी, मूर्तिकार, मेकअप कलाकार, संगीतकार, वादक, मंचकर्मी और तकनीकी कर्मचारी भी जुड़े होते हैं। पीढ़ियों से अनेक परिवार रामलीला से संबंधित अलग-अलग कलाओं को आगे बढ़ाते हैं।

आज एलईडी स्क्रीन, डिजिटल ध्वनि, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और विशेष प्रभावों ने मंच को भव्य बना दिया है। मगर चुनौती यही है कि तकनीक कथा पर हावी न हो जाए। रामलीला का आकर्षण उसके चमत्कार में कम और उसके भाव में अधिक है।

सामाजिक समरसता

रामलीला की सबसे बड़ी सामाजिक विशेषताओं में से एक है—सामूहिक सहभागिता। इसमें मोहल्ले, गांव और शहर का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। कोई कलाकार बनता है, कोई व्यवस्था संभालता है, कोई चंदा देता है और कोई दर्शक बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। विभिन्न समुदायों और सामाजिक वर्गों के लोग आयोजन से जुड़ते हैं। यही लोकपरंपरा की खूबसूरती है कि वह समाज को केवल दर्शक नहीं रहने देती, उसे सहभागी बना देती है।

आज की डिजिटल दुनिया में रामलीला जैसे आयोजन सामूहिक अनुभव की वह जगह हैं जहां लोग मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलकर एक-दूसरे के साथ बैठते, हंसते,भावुक होते हैं और कथा के साथ जुड़ते हैं।

आर्थिक गतिविधियों का बड़ा अवसर

रामलीला का एक खास आर्थिक पक्ष भी है, मंच सजता है तो स्थानीय कारीगरों को काम मिलता है। पोशाकें बनती हैं तो दर्जियों का काम बढ़ता है। मुकुट, गदा, धनुष-बाण और आभूषण तैयार होते हैं तो छोटे व्यवसायों को रोजगार मिलता है। मेले लगते हैं तो खिलौने, खान-पान, सजावटी वस्तुओं और दैनिक उपयोग की चीजों की बिक्री बढ़ती है। रामलीला मैदानों के पास अस्थायी दुकानों और स्थानीय सेवाओं से अनेक लोगों की आय होती है। इस दृष्टि से रामलीला केवल धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन मात्र नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला मौसमी उत्सव भी है।

बदलता समय, बदलती रामलीला

आज रामलीला के सामने सबसे बड़ी चुनौती मनोरंजन के बदलते माध्यम हैं। कभी पूरे परिवार के लिए रामलीला ही बड़ा सार्वजनिक मनोरंजन थी। अब मोबाइल, ओटीटी, सोशल मीडिया और डिजिटल वीडियो ने दर्शकों का ध्यान बांट दिया है लेकिन इसके बावजूद रामलीला खत्म नहीं हुई बल्कि उसने स्वयं को बदल दिया है। कहीं मंचन का सीधा प्रसारण होता है, कहीं सोशल मीडिया पर प्रचार होता है, कहीं डिजिटल प्रकाश और ध्वनि का प्रयोग होता है। युवा कलाकार नए अंदाज में संवाद बोल रहे हैं और आयोजन समितियां नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए प्रयोग कर रही हैं। जरूरत केवल इतनी है कि आधुनिकता के साथ मूल संवेदना सुरक्षित रहे। रामलीला यदि केवल तेज आवाज, चमकदार प्रकाश और महंगे विशेष प्रभावों की प्रतियोगिता बन गई तो उसका लोकस्वर कमजोर पड़ सकता है।

आज भी रामलीला जरूरी

रामलीला की प्रासंगिकता आज शायद पहले से अधिक है, क्योंकि हमारा समय सुविधा और सूचना से भरपूर होते हुए भी मूल्यों के संकट से जूझ रहा है। सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, परिवार में संवाद, समाज में सहिष्णुता और व्यवहार में संयम जैसे प्रश्न लगातार सामने हैं।

रामलीला इन प्रश्नों का कोई आधुनिक नीति-दस्तावेज तो नहीं देती, लेकिन प्रतीकों और पात्रों के माध्यम से मनुष्य को आईना जरूर दिखाती है। इसलिए जरूरी है कि रामलीला को केवल मनोरंजन या धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं अपितु उसके भीतर छिपे सामाजिक संदेश को समझा जाए।

रामलीला की असली सफलता तब होगी जब मंच से बाहर मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, छल, लोभ और हिंसा को भी पहचानने की कोशिश करे। अपने भीतर का रावण जलाना कठिन। शायद रामलीला की सबसे बड़ी प्रासंगिकता इसी कठिन काम की याद दिलाने में है। रामलीला इसलिए जीवित है क्योंकि वह हर पीढ़ी से पूछती है कि उसके समय का राम कौन है और उसके भीतर का रावण किस रूप में खड़ा है। यही प्रश्न उसे परंपरा से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक ले जाता रहेगा।

- डॉ. घनश्याम बादल

सबसे महत्वपूर्ण ...

गौतम चौधरी

फ्लाईदुबई हादसा : एक व्यक्ति का अपराध पूरे धार्मिक समाज की कसौटी नहीं हो सकती



कभी-कभी किसी घटना को लेकर हम खुद के चिंतन के आधार पर अपराधी ढुंढ लेते हैं लेकिन वास्तविक चित्र कुछ और होता है। आज के सोशल मीडिया युग में यह प्रक्रिया इतनी तेज हो गयी है कि कल्पना और परिकल्पना साफ तौर पर दिखने लगता है। ऐसे में तथ्य और सत्य का घालमेल बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ हाल के दिनों में कई घटनाओं में देखा गया है। अभी अभी 30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में हुई घटना के बाद कुछ ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है। इस घटना ने विमानन सुरक्षा के साथ-साथ एक गंभीर सामाजिक प्रश्न भी खड़ा कर दिया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार भारतीय मूल के कप्तान स्मित मच्छर और उनके ओमानी सह-पायलट हमाम अल-हम्मामी के बीच कॉकपिट में गंभीर झड़प हुई। इस दौरान विमान अचानक हजारों फीट नीचे गया। घायल कप्तान ने स्थिति संभालने की कोशिश की और यात्रियों तथा चालक दल की मदद से विमान को सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबूक में उतारा गया।

घटना की अंतरराष्ट्रीय जांच अभी जारी है। इसलिए इसके अंतिम कारण और उद्देश्य के बारे में निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी उचित नहीं होगी। फिर भी इस घटना से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ''एक व्यक्ति के कथित अपराध को उसके धर्म से जोड़कर पूरे समुदाय को कठघरे में खड़ा करना क्या उचित है?''रिपोर्टों में सामने आया है कि सह-पायलट के बारे में 2024 में सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंता सामने आई थी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया कि Oman Air में प्रशिक्षण के दौरान उसके पास कथित रूप से चरमपंथी सामग्री मिली थी और उसे कुछ समय के लिए उड़ान से अलग किया गया था। इसके बाद वह अलग-अलग विमानन संस्थाओं से जुड़ा और अंततः फ्लाईदुबई में सह-पायलट के रूप में काम करने लगा। यदि जांच में यह जानकारी सही साबित होती है तो सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि ''अंतरराष्ट्रीय विमानन व्यवस्था में सुरक्षा संबंधी ऐसी सूचना आगे कैसे पहुंचती है और उसकी पुष्टि कैसे होती है?'' यदि किसी पायलट के बारे में पहले गंभीर सुरक्षा चिंता दर्ज हो चुकी हो तो अगली एयरलाइन उसकी पृष्ठभूमि की जांच किस स्तर तक करती है? क्या विभिन्न देशों की विमानन कंपनियों और नियामक संस्थाओं के बीच सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने की पर्याप्त व्यवस्था है? क्या पायलट की पेशेवर योग्यता की जांच के साथ उसकी सुरक्षा पृष्ठभूमि की भी प्रभावी जांच होती है? ये प्रश्न किसी धर्म से संबंधित नहीं हैं। ये सीधे-सीधे ''विमानन सुरक्षा और यात्रियों के जीवन'' से संबंधित हैं। यदि जांच यह प्रमाणित करती है कि हमला किसी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित था तो उस विचारधारा की कठोर आलोचना होनी चाहिए। धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के प्रति किसी प्रकार की नरमी लोकतांत्रिक समाज के हित में नहीं है। मगर यहां एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है। ''किसी चरमपंथी विचारधारा की आलोचना और पूरे धर्म की निंदा एक ही बात नहीं है।''एक मुस्लिम व्यक्ति अपराध करता है तो उसका अपराध उसके व्यक्तिगत कृत्य और प्रमाणित विचारधारा के आधार पर तय होना चाहिए। उसी कसौटी पर हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को भी देखा जाना चाहिए। कानून व्यक्ति के अपराध को देखता है, उसकी पूरी धार्मिक आबादी को नहीं। यही सिद्धांत आतंकवाद से लड़ाई को भी मजबूत करता है क्योंकि आतंकवाद के वास्तविक स्रोत की पहचान तभी संभव है जब जांच धार्मिक पहचान और आपराधिक व्यवहार के बीच फर्क कर सके। इस घटना में भारतीय कप्तान स्मित मच्छर की भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण है। संकट की स्थिति में उन्होंने विमान को संभालने और यात्रियों की जान बचाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में उनके साहस और पेशेवर जिम्मेदारी की सराहना होनी चाहिए मगर उनकी वीरता को किसी दूसरे धर्म के विरुद्ध तर्क में बदलना उचित नहीं होगा। किसी व्यक्ति की वीरता का मूल्य उसके धर्म से नहीं, उसके कर्म से तय होता है। यदि एक व्यक्ति संकट में सैकड़ों लोगों की जान बचाता है तो वह अपने कर्म के कारण सम्मान का अधिकारी है। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपने अपराध के लिए कानून के सामने जवाब देना होगा।

प्रदेश के श्रम विभाग की प्रभावी पहल से बाल श्रमिकों को मिल रहा है,नया जीवन

किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहां श्रमिकों, बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधिकारों एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास का अर्थ केवल बड़ी इमारतें और सड़कें नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव है। इसी सोच के साथ जनपद हमीरपुर में श्रम विभाग द्वारा विगत 9 वर्षों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, बाल एवं बंधुआ श्रम उन्मूलन, व्यवस्थित कार्य परिस्थितियां तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किया गया है। श्रम विभाग की सक्रियता का परिणाम है कि जहाँ एक ओर बाल एवं बंधुआ श्रम के विरुद्ध लगातार कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी ओर हजारों श्रमिकों एवं छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़कर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कल्याणकारी नीतियों के तहत गत 9 साल की यात्रा केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि 535 बचपन को बचाने और हजारों परिवारों को सुरक्षित भविष्य देने की कहानी है। हमीरपुर जनपद में 499 सघन निरीक्षण से 535 बचपन को नया जीवन मिला। बाल एवं किशोर श्रमिकों के नियोजन को रोकने और बच्चों को शिक्षा एवं बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के उद्देश्य से संयुक्त टीमों द्वारा 499 सघन निरीक्षण किए गए। श्रम विभाग, पुलिस, चाइल्ड लाइन और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीमों ने ढाबों, होटलों, कारखानों, ईंट भट्टों और दुकानों पर छापेमारी की। निरीक्षणों के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से 535 बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया। ये वे बच्चे थे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें औजार थमा दिए थे। विभाग का प्रयास केवल इन बच्चों को श्रम से बाहर निकालने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास को भी सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इस कार्यवाई में अवमुक्त कराए गए सभी बच्चों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में नामांकन कराया गया और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया ताकि वे दोबारा बाल श्रम की ओर न जाएं। यह हमीरपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक-एक बच्चे को मुक्त कराना एक पूरे भविष्य को बचाना है। बंधुआ मुक्ति से सम्मानजनक जीवन की ओर श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जनपद में अन्य जनपदों से आए 18 घोषित बंधुआ श्रमिकों को अवमुक्त करा के पुनर्वास की कार्रवाई भी की गई। ये श्रमिक कर्ज के जाल में फंसकर बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर थे। विभाग ने श्रमिकों को शोषण एवं बंधन से मुक्त कराने के साथ उन्हें सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा में वापस लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्हें मुक्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता, आवासीय सुविधा और रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया। यह कार्रवाई इस संदेश के साथ की गई कि जनपद में किसी भी प्रकार के बंधुआ श्रम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन श्रमिकों को उनका हक दिलाने के लिए विभाग ने श्रम कानूनों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया। आनुतोषिक भुगतान अधिनियम के तहत 11 निरीक्षणवेतन संदाय अधिनियम में 11 निरीक्षण समान पारिश्रमिक अधिनियम में 05 निरीक्षण मातृत्व हितलाभ अधिनियम में 02 निरीक्षण संविदा श्रम अधिनियम में 02 निरीक्षण बोनस भुगतान अधिनियम के तहत 01 निरीक्षण किया गया।

जरा हटके

बलरामपुर के विशिष्ट ...

डॉ0 सीमा गुप्ता

बलरामपुर के पारंपरिक उत्पादों को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच: 'एक जनपद-एक उत्पाद' योजना से सशक्त हो रहे स्थानीय उद्यम



ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में बलरामपुर जनपद के पारंपरिक उत्पादों एवं विशिष्ट स्थानीय व्यंजनों का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। 25 से 29 सितंबर तक आयोजित इस बहुउद्देशीय प्रदर्शनी में जिले की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक पाक कला को देश-विदेश के व्यापारिक प्रतिनिधियों, निर्यातकों एवं आम आगंतुकों के समक्ष प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत बलरामपुर के स्थानीय हुनर, पारंपरिक मिष्ठान निर्माण एवं शिल्पकला को संगठित बाजार से जोड़ने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आयोजित इस सहभागिता का मुख्य उद्देश्य जनपद के सूक्ष्म उद्यमियों, मिष्ठान निर्माताओं और पारंपरिक कारीगरों की आय में टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करना है। ट्रेड शो में बलरामपुर के प्रसिद्ध कलाकंद और नारियल की बर्फी को आगंतुकों ने अपनी विशिष्ट गुणवत्ता, पारंपरिक निर्माण विधि और अप्रतिम स्वाद के कारण अत्यधिक सराहा। इसके साथ ही, बलरामपुर के सुप्रसिद्ध पारंपरिक स्वाद 'बालाजी की चाट' और स्थानीय मूंज के शिल्प और कृतियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनी का प्राथमिक ध्येय केवल उत्पादों का प्रदर्शन करना नहीं, अपितु जनपद के अनौपचारिक क्षेत्र के उत्पादकों को आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, थोक खरीदारों और संस्थागत बाजार तंत्र से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना था। इस पहल से स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन के साथ-साथ युवाओं और कारीगरों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

भौगोलिक दृष्टि से तराई क्षेत्र में स्थित बलरामपुर जनपद दुग्ध उत्पादन, कृषि संपदा और प्राकृतिक वनोपज में विपुल संभावनाएं समेटे हुए है। जिला प्रशासन द्वारा इन पारंपरिक और प्राकृतिक क्षमताओं को सुव्यवस्थित व्यावसायिक उत्पादकता में परिवर्तित करने हेतु एक समग्र कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। पारंपरिक खाद्य उत्पादों की शेल्फ-लाइफ, स्वच्छता मानकों और गुणवत्ता संवर्धन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग द्वारा विशेष तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसए-आई) के मानकों के अनुरूप उत्पादन और स्वच्छता प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। स्थानीय मिष्ठान निर्माताओं एवं खाद्य उद्यमियों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा विपणन के तौर-तरीकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। आकर्षक और मानक फूड-ग्रेड पैकेजिंग के माध्यम से बलरामपुर के कलाकंद एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों को महानगरों के संगठित रिटेल स्टोर्स तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए गए हैं। 'ओडीओपी कौशल संवर्धन एवं टूलकिट वितरण योजना' के अंतर्गत जिले के पारंपरिक कारीगरों एवं हलवाइयों के तकनीकी उन्नयन हेतु नियमित प्रशिक्षण सत्र संचालित किए जा रहे हैं। आधुनिक उपकरणों एवं उन्नत टूलकिट्स के निःशुल्क वितरण से निर्माण क्षमता में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता और स्वच्छता भी सुदृढ़ हो रही है। ग्रामीण अंचल में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को गति देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को इन पारंपरिक उद्यमों से सक्रियता से संबद्ध किया गया है। स्थानीय उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन श्रृंखला में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

पूंजीगत बाधाओं को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत उद्यमियों को मार्जिन मनी सब्सिडी और सुलभ संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बैंकों के साथ सतत समन्वय स्थापित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुद्रा योजना के माध्यम से सुगम वित्तीय लिंकेज सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

बिचौलियों की निर्भरता को समाप्त कर उत्पादकों को उनके उत्पाद का अधिकतम मूल्य दिलाने हेतु डिजिटल कॉमर्स का विस्तार किया जा रहा है। जनपद के पंजीकृत उद्यमियों और कारीगरों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे राष्ट्रीय मंचों पर तेजी से ऑनबोर्ड कराया जा रहा है।

उत्पादों के मानकीकरण और परीक्षण के उद्देश्य से कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। यह साझा अवसंरचना छोटे कारीगरों को गुणवत्ता परीक्षण, कोल्ड चेन, उन्नत पैकेजिंग और मशीनरी की सुविधाएं न्यूनतम लागत पर एक ही छत के नीचे सुलभ कराएगी।

बलरामपुर के विशिष्ट उत्पादों की प्रामाणिकता और भौगोलिक पहचान की वैधानिक सुरक्षा के लिए भौगोलिक उपदर्शन (जीआई टैग) दिलाने की प्रक्रिया को भी संस्थागत स्तर पर गति प्रदान की जा रही है। जीआई प्रमाणीकरण मिलने से जनपद के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर विशिष्ट साख और बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के माध्यम से प्राप्त व्यापारिक संपर्कों और क्रय आदेशों के समयबद्ध अनुपालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जा रहा है। इससे स्थानीय सूक्ष्म इकाइयों को थोक ऑर्डर्स की आपूर्ति में लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता नियंत्रण और व्यापारिक सुगमता का निरंतर संबल मिलता है।

पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रमुख बैराजों के बदले गेट, आपदा से निपटने के लिए स्पेयर गेट भी किए तैयार

योगी सरकार ने बदली यूपी की जर्जर जल संरचनाओं की तस्वीर

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास, सिंचाई के पानी की एक-एक बूंद का हो बेहतर उपयोग
- 60 से 70 फीट गहरे पानी में गेट बदलकर यूपी ने रचा तकनीकी कीर्तिमान
- बैराज, बांध और रेगुलेटरों के गेटों के आधुनिकीकरण से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को मिली नई ताकत

प्रबंधन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की प्रमुख जल संरचनाओं बैराज, बांध, हेड रेगुलेटर और अन्य जल यांत्रिक संरचनाओं के गेटों के निर्माण और प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ बाढ़ और आपदा की स्थिति में जल संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनिल गर्ग ने बताया कि योगी सरकार की पहल से पुरानी और जर्जर हो चुकी जल संरचनाओं को आधुनिक तकनीक से नया जीवन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से उपयोग में होने से कई महत्वपूर्ण बैराजों और बांधों के गेट समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है, ताकि जल संरचनाओं के संचालन में किसी तरह की बाधा न आए और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था सुचारु बनी रहे। पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में बड़े पैमाने पर गेटों के प्रतिस्थापन का काम किया गया है।





पानी के भीतर गेट बदलना बड़ी तकनीकी उपलब्धि

प्रमुख सचिव अनिल गर्ग ने बताया कि दिल्ली स्थित ओखला बैराज के 27 में से 18 गेट बदले जा चुके हैं और आपात स्थिति के लिए तीन स्पेयर गेट भी तैयार रखे गए हैं। भीमगौड़ा बैराज, हरिद्वार के 22 में से आठ खराब गेट बदले गए हैं। इन गेटों का निर्माण विभाग की आईएसओ प्रमाणित कार्यशालाओं, बरेली और झांसी में किया गया है। रामपुर स्थित कैनरी बैराज के 15 में से नौ, गाजियाबाद स्थित हिंडन बैराज के सभी आठ और अन्य प्रमुख जल संरचनाओं में भी पुराने गेटों के प्रतिस्थापन का काम किया गया है। कई बांधों और बैराजों में अतिरिक्त स्पेयर गेट भी सुरक्षित रखे गए हैं, जिससे आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।प्रदेश में पहली बार अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पानी के भीतर स्थित गेटों को आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक और विशेषज्ञ गोताखोरों की मदद से सफलतापूर्वक बदला गया है। ललितपुर स्थित माताटीला बांध, मेजा-जरगो लिंक रेगुलेटर और कचनौदा बांध में लगभग 60 से 70 फीट की गहराई में स्थित अंडर-स्लूइस गेटों का पानी के भीतर प्रतिस्थापन किया गया।

नगराम में 7.288 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

तमसा संकेत, संवाददाता



लखनऊ। नगराम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7.288 किलोग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है, बरामद किया है। इसके अलावा एक प्लेटिना मोटरसाइकिल, 2100 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक सोमवार को नगराम पुलिस टीम हरदोइया बैराज से नहर पटरी रोड पर ग्राम चन्दीदीन घोड़सारा के पास नहर पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान काले-नीले रंग की प्लेटिना मोटरसाइकिल संख्या UP41 BH 4129 को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में आरोपियों के पास से गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश कुमार गौतम (20) निवासी ग्राम करोरा, थाना नगराम और अंकुश कुमार कोरी उर्फ नवीन (19) निवासी ग्राम हुसैनाबाद, थाना लोनीकटरा, बाराबंकी के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लखनऊ के आसपास के जिलों से गांजा लाकर छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। बरामदगी के आधार पर नगराम थाने में मु.अ.सं. 147/2026, धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कार्रवाई पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देश, डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक के निर्देशन और एसीपी मोहनलालगंज राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक नगराम अंजनी कुमार सिंह की टीम ने की।

फास्ट न्यूज

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में ज्ञापन

गाजियाबाद। गाजियाबाद में परमार्थ सेवा ट्रस्ट की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित था। संस्था के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की छवि खराब करने और उन्हें पद से हटाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि ज्ञानेश कुमार ने कई राज्यों में निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराए हैं।

रेपिस्ट पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या की

मेरठ। मेरठ में सोमवार शाम करीब 3 बजे रेपिस्ट पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह अपने घर से करीब 500 मीटर दूर साली के घर पहुंचा। कहा- तेरी बहन को मार डाला। इसके बाद मौके से फरार हो गया। आरोपी करीब डेढ़ साल पहले रेप के मामले में जेल गया था। 8 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। पुलिस के मुताबिक, ससुर के जमानत ना कराने पर वह नाराज था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो जाता था। इसी नाराजगी में उसने पत्नी को मार डाला।

मेरठ में डीएवी रीजनल स्पोर्ट्स का हुआ समापन

मेरठ। डीएवी पब्लिक स्कूल, मेरठ की ओर से आयोजित डीएवी रीजनल स्पोर्ट्स 2026 प्रतियोगिता 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी। तीन दिन तक चली प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हुआ। समापन समारोह में राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया और डीएवी स्कूल्स यूपी जोन-ए की क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अल्पना शर्मा मौजूद रहीं। प्रतियोगिता में अलग-अलग डीएवी स्कूलों के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई।

उचित समस्या को लेकर दूसरी बार फरियादी आए तो जवाबदेही तय : योगी

पीड़ित की संतुष्टि सरकार का ध्येय, प्रशासन हर उचित समस्या का कराए समयबद्ध निस्तारण

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' में दूरदराज से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों को समाधान का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन हर उचित समस्या का समयबद्ध निस्तारण कराए, यदि पीड़ित एक ही समस्या को लेकर दूसरी बार आया और वह समस्या वास्तविक रही तो जवाबदेही तय होगी। पीड़ित की संतुष्टि सरकार का ध्येय है। यदि पीड़ित की समस्या वास्तविक है और समय से उसका निस्तारण नहीं हो पाया, तो यह अक्षम्य है। मुख्यमंत्री ने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचकर उनकी पीड़ा जानी और आश्वस्त किया कि सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 'जनता दर्शन' में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और समयबद्ध/पारदर्शी निस्तारण कराएं। इस दौरान कुछ लोगों ने जमीन जबरन कब्जा कर लिए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी दबंग ने किसी गरीब की जमीन हड़पी है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। जमीन अवैध या जबरन कब्जे से मुक्त होनी चाहिए। जमीन कब्जामुक्त कराने के साथ जबरन कब्जा करने वालों को कड़ा कानूनी सबक सिखाया जाए। पीड़ित को न्याय और दोषियों को सजा दिलाएं।





अब शहर की दूरी नहीं रोकेगी पढ़ाई, गांव में खुला ज्ञान का डिजिटल द्वार: सीएम योगी

2017 के पहले महज 76, अब 57,600 गांवों तक पहुंची डिजिटल लाइब्रेरी : मुख्यमंत्री

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को डिजिटल लाइब्रेरी से ग्रामीण क्षेत्रों में आए बदलाव से अवगत कराते हुए कहा कि अब शहर की दूरी पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती। प्रदेश के 57,600 गांवों तक डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचने से ज्ञान का डिजिटल द्वार खुला है। संसाधन करीब आए तो सपनों की राह भी आसान हुई है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि संसाधन करीब आए तो सपनों की राह भी आसान हुई। बच्चे और युवा यहां अध्ययन कर रहे हैं, ई-लर्निंग से जुड़ रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को नई धार दे रहे हैं। जो समय और पैसा पहले शहर आने-जाने में लगता था, वह अब उनकी पढ़ाई में लग रहा है। सीएम ने लिखा कि 2012-16 में पर्याप्त सरकारी निधि होने के बावजूद 6.22 लाख बच्चों को पाठ्यपुस्तकें और 97 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिली। शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता से लेकर उनकी पहुंच तक, उत्तर प्रदेश ने लंबी दूरी तय की है। अभिभावकों के लिए भी यह बदलाव भरोसे का आधार बना है। उनके बच्चों को आधुनिक शैक्षिक संसाधनों के लिए अब गांव से दूर नहीं जाना पड़ रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम पंचायत डिजिटल लाइब्रेरी पहल का परिणाम धरातल पर है। ग्राम पंचायत सचिवालय अब प्रशासनिक सेवाओं के साथ ज्ञान और तकनीक के केंद्र के रूप में भी नई भूमिका निभा रहे हैं। खसहा मोहम्मदपुर की यह डिजिटल लाइब्रेरी बदलाव की जीवंत तस्वीर है। गांव बदल रहा है, पढ़ाई का परिवेश बदल रहा है और ज्ञान की रोशनी अब बच्चों के द्वार तक पहुंच रही है।

अब गांव में ही पुस्तक और डिजिटल कंटेंट

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर 2017 के पहले की स्थिति भी बताई। उन्होंने लिखा कि पहले गांव के किसी बच्चे को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होती थी तो किताबों और बेहतर संसाधनों के लिए शहर की ओर देखना पड़ता था। दूरी समय भी लेती थी और पैसा भी। अब बहराइच के तेजवापुर ब्लॉक के खसहा मोहम्मदपुर में यही दूरी डिजिटल लाइब्रेरी ने कम कर दी है। ग्राम पंचायत सचिवालय में तैयार यह लाइब्रेरी किताब और कंप्यूटर, परंपरागत अध्ययन और आधुनिक तकनीक को एक छत के नीचे जोड़ रही है। यहां कंप्यूटर, प्रिंटर, हाई-स्पीड इंटरनेट, वाई-फाई, स्मार्ट टीवी और सीसीटीवी की सुविधा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट का साहित्य भी उपलब्ध है। यानी पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए या तैयारी के लिए डिजिटल कंटेंट, दोनों अब गांव में ही सुलभ हैं।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह बदलाव केवल एक गांव तक सीमित नहीं है। 2017 से पहले ई-लाइब्रेरी की पहुंच राज्य और जिला स्तर के लगभग 76 स्थानों तक सीमित थी, आज डिजिटल लाइब्रेरी 57,600 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। डिजिटल शिक्षा को केवल स्कूलों तक सीमित न रखते हुए लगभग 60 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में विकसित होगी इंटरनेशनल ट्रेड सिटी

चीन की यीवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की तर्ज पर होगा विकास

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने और प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया के बाजार से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में चीन की यीवू (Yiwu) इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की तर्ज पर इंटरनेशनल ट्रेड सिटी विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। हाल में संपन्न यीडा की बोर्ड मीटिंग में इस परियोजना की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित सिटी को व्यापार, उद्योग और निर्यात के एक नए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इंटरनेशनल ट्रेड सिटी के माध्यम से क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादों को एक ऐसा संगठित और स्वीकृत बाजार उपलब्ध होगा, जहां उत्पादों का प्रदर्शन, बिक्री और निर्यात एक ही प्लेटफॉर्म से किया जा सकेगा। इससे स्थानीय उद्यमियों और औद्योगिक इकाइयों को नए खरीदारों तक पहुंच बनाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे।

योगी सरकार की औद्योगिक नीति का प्रमुख लक्ष्य उत्तर प्रदेश को केवल बड़े निवेश का केंद्र बनाना ही नहीं, बल्कि यहां तैयार होने वाले उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना भी है। इंटरनेशनल ट्रेड सिटी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। प्रस्तावित इंटरनेशनल ट्रेड सिटी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े औद्योगिक उत्पादों के लिए व्यवस्थित बाजार और प्रदर्शन की सुविधा विकसित किए जाने की परिकल्पना है। इससे उत्पादकों को अपने उत्पाद सीधे देश-विदेश के खरीदारों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही निर्यातकों और संभावित विदेशी खरीदारों के बीच व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में प्रदेश के 2.66 लाख स्कूलों में 1.86 लाख में शुरू हुई प्रक्रिया

योगी सरकार में स्वच्छ-हरित विद्यालयों का बढ़ा कारवां

1.79 लाख का पंजीकरण

1,62,054 विद्यालयों ने दर्ज कराई सहभागिता, प्रदेश का अंतिम पूर्णता प्रतिशत 60.83 प्रतिशत

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में स्वच्छता, हरित परिवेश और पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक सहभागिता सामने आई है। 'स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग' यानी एसएचवीआर (SHVR—स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग) 2026-27 में 5 अक्टूबर तक प्रदेश के कुल 2,66,408 विद्यालयों में 1,86,196 में प्रक्रिया शुरू, 1,79,793 विद्यालयों का पंजीकरण और 1,62,054 विद्यालयों द्वारा सहभागिता पूर्ण की गई है। प्रदेश का अंतिम पूर्णता प्रतिशत 60.83 प्रतिशत दर्ज हुआ है। एसएचवीआर 2026-27 की यह स्थिति उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में स्वच्छता, हरित परिवेश और पर्यावरणीय चेतना के प्रति व्यापक सहभागिता को रेखांकित करती है। प्रदेश के अनेक जनपदों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई है। एसएचवीआर के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छ एवं हरित वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित गतिविधियों और मानकों में विद्यालयों की सहभागिता को दर्ज किया जाता है। जनपदवार रिपोर्ट प्रदेश के सभी 75 जनपदों के विद्यालयों की स्थिति को दर्शाती है। जनपदवार आंकड़ों में कानपुर देहात 83.17% अंतिम पूर्णता प्रतिशत के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जनपद के कुल 2,876 विद्यालयों में से 2,392 विद्यालयों ने पूर्णता दर्ज की है। मुजफ्फरनगर 82.24% के साथ दूसरे और भदोही 77.62% के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद कौशांबी 75.22% और ललितपुर 73.78% के साथ शीर्ष पांच में शामिल हैं। अंतिम पूर्णता प्रतिशत के आधार पर टॉप-10 में कानपुर देहात (83.17%), मुजफ्फरनगर (82.24%), भदोही (77.62%), कौशांबी (75.22%), ललितपुर (73.78%), बाराबंकी (73.52%), रामपुर (71.90%), मऊ (71.50%), बुलंदशहर (70.25%) और सहारनपुर (68.90%) शामिल हैं।

पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सहभागिता

पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विद्यालयों की व्यापक सहभागिता दर्ज हुई है। वाराणसी में 67.58%, मिर्जापुर में 68.29%, सोनभद्र में 68.51%, गोरखपुर में 60.83%, बुलंदशहर में 70.25% और सहारनपुर में 68.90% अंतिम पूर्णता प्रतिशत दर्ज किया गया है। इन आंकड़ों से विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की दिशा में विद्यालयों की सक्रिय भागीदारी सामने आती है। प्रदेश के कुल 2,66,408 विद्यालयों में 1,86,196 विद्यालयों में एसएचवीआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि 1,79,793 विद्यालयों ने पंजीकरण कराया और 1,62,054 विद्यालयों ने इसे पूर्ण किया। यह आंकड़ा प्रदेशभर में एसएचवीआर 2026-27 के प्रति विद्यालयों की व्यापक और सक्रिय सहभागिता को रेखांकित करता है।

● कोट:

स्वच्छ एवं हरित विद्यालय स्वस्थ और जागरूक पीढ़ी की आधारशिला हैं। एसएचवीआर के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छता, हरित परिवेश और पर्यावरणीय चेतना को और मजबूत किया जा रहा है।

संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा

● कोट:

एसएचवीआर विद्यालयों को स्वच्छता और पर्यावरणीय मानकों के प्रति सक्रिय बनाने का प्रभावी माध्यम है। व्यापक सहभागिता से स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों की दिशा में सकारात्मक बदलाव को गति मिलेगी।

मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

उपलब्धी: चयन से वंचित और प्रवेश न ले पाने वाले छात्रों को फिर विकल्प भरने का मौका, 6 से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन

आईटीआई प्रवेश का पांचवां चरण शुरू

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश की प्रक्रिया के पांचवें चरण के लिए छात्रों को एक और अवसर दिया गया है। प्रवेश के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में चयनित नहीं हो सके छात्र या चयन होने के बाद भी किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाने वाले अभ्यर्थी अब दोबारा अपने विकल्प दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। इसके बाद वे उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार अपनी पसंद के संस्थान और व्यवसाय के संशोधित विकल्प भर सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत छात्रों को अपने आवेदन में कुछ जरूरी जानकारियां दोबारा पंजीकृत करने की सुविधा भी दी गई है। इनमें लिंग, उपवर्ग और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी शामिल है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे विकल्प भरने से पहले उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी अच्छी तरह देख लें और अपनी पसंद के संस्थान एवं व्यवसाय का चयन प्राथमिकता के आधार पर करें। जिन छात्रों ने पहले आवेदन किया था लेकिन अब नए विकल्प दर्ज नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों को उनके मूल आवेदन पत्र में पहले से दर्ज विकल्पों के आधार पर ही पांचवें चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। हालांकि, यदि छात्र अपने पसंदीदा संस्थान या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित समय के भीतर संशोधित विकल्प दर्ज करने होंगे। नए विकल्प दर्ज करने से छात्रों को उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुसार अपनी प्राथमिकता बदलने का अवसर मिलेगा।

राजकीय आईटीआई में पहले प्रवेश ले चुके लेकिन किसी कारणवश अपना नाम कटवा चुके छात्रों के लिए भी इस चरण में आवेदन का रास्ता खोला गया है।

नए विकल्प नहीं भरे तो पुराने आवेदन से होगा आवंटन

यदि कोई छात्र नए विकल्प दर्ज नहीं करता है तो उसे उसके मूल आवेदन में दिए गए विकल्पों के आधार पर ही पांचवें चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ऐसे में छात्रों को सलाह दी गई है कि वे उपलब्ध रिक्त सीटों और पसंदीदा संस्थानों की जानकारी देखकर जरूरत के अनुसार अपने विकल्प संशोधित करें।

रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध

चौथे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद बची हुई सीटों का विवरण भी छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। रिक्त सीटों की जानकारी जिलावार, संस्थानवार और व्यवसायवार उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी यह जानकारी परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा संबंधित राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यालय से भी रिक्त सीटों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रिक्त सीटों की जानकारी के आधार पर छात्र यह तय कर सकेंगे कि किस संस्थान में कौन सा व्यवसाय उपलब्ध है। इससे उन्हें पांचवें चरण में विकल्प भरने में सुविधा होगी।

11 अक्टूबर की आधी रात तक मौका

ऑनलाइन आवेदन और विकल्प भरने की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से 11 अक्टूबर 2026 की आधी रात तक उपलब्ध रहेगी। चौथे चरण के बाद बची रिक्त सीटों का जिलावार, संस्थानवार और व्यवसायवार विवरण परिषद की वेबसाइट www.scvtup.in और संबंधित संस्थानों के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। सभी राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संस्थान में रिक्त सीटों की व्यवसायवार अद्यतन जानकारी सार्वजनिक सूचना पट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। इसका उद्देश्य छात्रों को उपलब्ध सीटों और विकल्पों की सही जानकारी देना है, ताकि वे अपनी पसंद के अनुसार आवेदन कर सकें।

आईटीआई सत्र 2026-27 के पंचम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू

रिक्त सीटों के लिए 6 से 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.), उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के पंचम चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। चतुर्थ चरण की प्रवेश प्रक्रिया 03 अक्टूबर 2026 को संपन्न होने के उपरांत रिक्त बची सीटों के सापेक्ष राजकीय आई०टी०आई० के पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों से नवीन विकल्प तथा राजकीय व निजी संस्थानों हेतु नवीन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के अधिशासी निदेशक (एस.सी.वी.टी.) अभिषेक सिंह ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में अचयनित अथवा चयनित होने के बाद भी प्रवेश से वंचित अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपनी पंजीकरण संख्या एवं जन्मतिथि दर्ज कर रिक्त व्यवसायों व इच्छित संस्थानों का पुनरीक्षित विकल्प भर सकते हैं। इसके साथ ही लिंग, उपवर्ग एवं शैक्षिक अर्हता को भी पुनः पंजीकृत किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा नवीन विकल्प पंजीकृत नहीं कराया जाता है, तो उनके मूल आवेदन में दिए गए विकल्पों के आधार पर ही पंचम चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजकीय संस्थानों में पूर्व में प्रवेशित किंतु किन्हीं कारणों से नाम कटा चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजकीय एवं निजी संस्थानों के लिए नए सिरे से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर जाकर पहले अपना फॉर्म भरना होगा। इसके पश्चात डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग अथवा यूपीआई के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त किया जा सकेगा। पंजीकरण शुल्क के रूप में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 300 रुपये, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 250 रुपये तथा समस्त महिला अभ्यर्थियों हेतु 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

आगरा के वरिष्ठ नेता को मिला मौका, 2027 से पहले संगठन में बढ़ेगा स्थानीय नेतृत्व का कद

भाजपा ने रामप्रताप सिंह चौहान को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी

घोषणा

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। भाजपा ने आगरा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के इस फैसले के बाद आगरा भाजपा में खुशी का माहौल है। चौहान वर्तमान में भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं और संगठन में लंबे अनुभव वाले नेताओं में उनकी गिनती होती है। जून 2026 में घोषित भाजपा की नई प्रदेश टीम में उन्हें लगातार दूसरी बार प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में

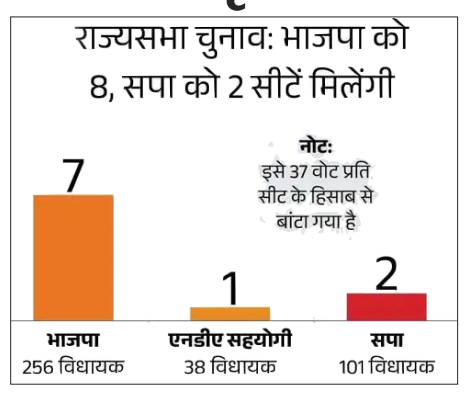
रामप्रताप सिंह चौहान का राजनीतिक सफर भाजपा संगठन से जुड़कर आगे बढ़ा। वर्ष 1991 से 1994 के बीच उन्होंने भाजयुमो में मंडल अध्यक्ष के तौर पर काम किया। इसके बाद वह भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष, ब्रज प्रांत प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे पदों पर रहे। वर्ष 2006-07 में उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 2007 से 2012 तक ब्रज क्षेत्र महामंत्री और 2013 से 2016 तक प्रदेश मंत्री रहे। संगठन में लगातार सक्रिय रहने के बाद वर्ष 2017 में भाजपा ने उन्हें एत्मादपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा।



रामप्रताप सिंह चौहान ने एत्मादपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया। हालांकि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद संगठन में उनकी भूमिका और बढ़ी। वर्ष 2023 में उन्हें भाजपा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। जून 2026 में घोषित नई प्रदेश कार्यकारिणी में उन्हें एक बार फिर प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली। अगस्त 2026 में उन्हें भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया।

राज्यसभा चुनाव में 37 वोट का गणित

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। इनमें सात सीटें खाली होने के कारण फिलहाल 396 विधायक हैं। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होने की स्थिति में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के वोटों का फॉर्मूला 396÷11+1 होगा। इस हिसाब से 396 को 11 से भाग देने पर 36 आता है और उसमें एक जोड़ने पर 37 वोट मिलते हैं। यानी राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत होगी। अगर भाजपा और सपा अपने अतिरिक्त प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारते हैं और संख्या बल में कोई बदलाव नहीं होता है, तो भाजपा के आठ और सपा के दो प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने की स्थिति बन सकती है। हालांकि अतिरिक्त प्रत्याशी मैदान में आने पर चुनाव की स्थिति में दोनों खेमों के वोटों का गणित बदल सकता है और प्रथम वरीयता वोट अहम भूमिका निभाएंगे।



आगरा की राजनीति के लिए अहम फैसला

रामप्रताप सिंह चौहान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने को आगरा और ब्रज क्षेत्र की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वह लंबे समय से इस क्षेत्र में भाजपा संगठन के लिए सक्रिय रहे हैं।

जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री और विधायक तक की जिम्मेदारी संभाल चुके चौहान को अब उच्च सदन भेजने की तैयारी है।

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आगरा के स्थानीय नेता को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने से क्षेत्रीय संगठन को भी राजनीतिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पार्टी कार्यकर्ताओं में इसे संगठन में लंबे समय से सक्रिय स्थानीय नेतृत्व को मिले बड़े अवसर के तौर पर देखा जा रहा है।

अतीक का शूटर अरमान चेहरा ढंककर कोर्ट पहुंचा

उमेश पाल की हत्या में गिरफ्तारी हुई, बिहार पुलिस वापस ले जाएगी

तमसा संकेत, एजेंसी



प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के शूटर अरमान को पुलिस ने सोमवार शाम करीब 4:15 बजे प्रयागराज कोर्ट में पेश किया। स्पेशल जज एससी-एसटी मयंक कुमार की कोर्ट ने अरमान को 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। अब प्रयागराज पुलिस कोर्ट में अरमान को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल करेगी। दरअसल, उमेश पाल हत्याकांड में अरमान को प्रयागराज पुलिस ने सोमवार को ऑफिशियली गिरफ्तार किया है। वहीं, कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार पुलिस अरमान को अपने साथ ले जाएगी और गयाजी जेल में दाखिल करेगी। कोर्ट से अरमान की रिमांड मिलने पर उसे प्रयागराज पुलिस के हवाले कर देगी। इससे पहले कोर्ट में पेश करने के दौरान अरमान की सुरक्षा में 40 पुलिसकर्मी साथ रहे। अरमान का चेहरा सफेद गमछे से ढंका गया था। मीडिया ने अरमान से पूछा- शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम कहां हैं? लेकिन, अरमान ने इन सवालों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अरमान की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भी 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। इनमें महिला पुलिस, PAC, 3 ACP समेत बिहार पुलिस के कमांडों भी शामिल रहे। अरमान 5 लाख का इनामी है। वह पिछले 3 साल से बिहार की गयाजी जेल में बंद था। वहां से अरमान को ट्रांजिट रिमांड पर प्रयागराज लाया गया था।

फास्ट न्यूज

आगरा में 3 दिन हाईवे पर वाहनों की नो एंट्री

आगरा। आगरा के भावना एस्टेट में 7 से 9 अक्टूबर तक जनकपुरी महोत्सव होगा। आयोजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। तीनों दिन दोपहर 3 बजे से रात 1 बजे तक नेशनल हाईवे-19 पर मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। रैपुरा जाट दक्षिणी बाईपास, मथुरा सीमा से कुबेरपुर कट तक ट्रक और दूसरे बड़े वाहनों को हाईवे पर नहीं जाने दिया जाएगा।

मुरादाबाद में फिर दिखा तेंदुआ

मुरादाबाद। मुरादाबाद के छजलैट क्षेत्र के रामनगर उर्फ रमपुरा गांव में देर रात तेंदुआ दिखाई दिया। फूलपुर जाने वाले रास्ते पर कुएं के पास ग्रामीणों ने तेंदुए को घूमते देखा। तेंदुए की आवाज सुनकर लोग डर गए और रात में घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ गांव के आसपास ही घूम रहा है। इससे बच्चों, महिलाओं और पालतू मवेशियों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। किसानों में भी खेतों पर जाने को लेकर डर बना हुआ है ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए की मौजूदगी के कारण रात में गांव में दहशत का माहौल है।

घर में घुसकर दबंगों ने 2 युवकों को पीटा

आगरा। आगरा में 4 युवकों ने घर के बाहर खड़े दो युवकों पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया।

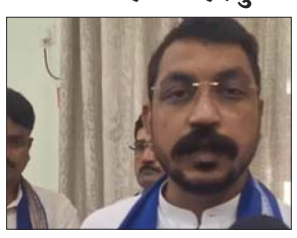
मारपीट से बचने के लिए दोनों युवक व्यापारी के घर के अंदर भागे।

हमलावर भी उनका पीछा करते हुए घर में घुस गए। इसके बाद एक युवक पर लाठी-डंडों से कई वार किए। सिर और पीठ पर किए गए हमले की पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

रातोंरात बढ़ जाता है चुनाव आयोग का वोट परसेंट

आगरा में सांसद चंद्रशेखर बोले- बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव

तमसा संकेत, एजेंसी



आगरा। आजाद समाज पार्टी (ASP) के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा- हमें जानकारी होती है कि 65% वोटिंग हुई है, लेकिन 2-3 दिन बाद चुनाव आयोग का आंकड़ा 70% वोटिंग का आता है तो ये रातोंरात 5% वोट कैसे बढ़ जाता है। उन्होंने कहा-बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जनता भी बैलेट पेपर से वोटिंग चाहती है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा-2027 के चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं कर रही। उनका गठबंधन जनता के साथ है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को अपनी आजाद समाज पार्टी के शिक्षक MLC प्रत्याशी दक्ष यादव के नामांकन के लिए आगरा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा-ज्ञानेश कुमार बदल के रूपेश कुमार आएं, रूपेश कुमार बदल के सोमेश कुमार आएं..XYZ कोई भी आए, जब तक प्रक्रिया नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जिस दिन वोट पड़ते हैं, उसके 2-3 दिन बाद आंकड़ा आता है कि 5% वोट बढ़ गए। हमें पता होता है कि 65% वोट पड़े हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि 70% वोट पड़े। ये 5% वोट कहां से बढ़ जाते हैं रातों रात।

आगरा यूनिवर्सिटी में घुसकर 2 छात्रों के सिर फोड़े

क्लासमेट से विवाद हुआ था, स्टूडेंट बोले-20 से ज्यादा लोगों को बुलाकर पिटवाया

तमसा संकेत, एजेंसी



आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर में सोमवार को दिनदहाड़े छात्रों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। गाली-गलौज के बाद बाहर से आए 20 से अधिक युवकों ने कैंपस में घुसकर बीएससी के दो छात्रों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर में चोटें आई हैं। घटना के बाद विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, खंदारी परिसर में बीएससी की पढ़ाई कर रहे आलोक और दिनेश की क्लास में अमित नाम का छात्र भी पढ़ता है। सोमवार सुबह किसी बात को लेकर आलोक और अमित के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच गाली-गलौज हुई और आरोप है कि अमित ने आलोक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अमित ने फोन कर अपने भाई और दोस्तों को बुला लिया।

बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में 20 से अधिक युवक कैंपस के बाहर पहुंच गए। जैसे ही आलोक और दिनेश क्लास से बाहर निकले, युवकों ने उन्हें घेर लिया और परिसर के अंदर ही दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोनों छात्रों के सिर में गंभीर चोटें आईं। देखते ही देखते दोनों लहूलुहान हो गए। घटना के दौरान कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रोफेसरों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और किसी तरह विवाद को शांत कराया। घटना की सूचना मिलने पर न्यू आगरा थाना पुलिस विश्वविद्यालय पहुंची। पुलिस घायल छात्रों को थाने ले गई। दोनों

सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी पर उठे सवाल

घटना के दौरान कैंपस में सुरक्षा गार्डों की मौजूदगी के बावजूद बाहरी युवकों के अंदर घुसकर मारपीट करने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्य गेट पर तीन से चार सुरक्षा गार्ड तैनात रहने के बावजूद 20 से अधिक बाहरी युवक परिसर के अंदर कैसे पहुंच गए। छात्रों का कहना है कि यह कैंपस में बाहरी लोगों के घुसने और मारपीट की पहली घटना नहीं है। उनका दावा है कि इससे पहले भी कई बार बाहरी लोग परिसर में घुसकर छात्रों से मारपीट कर चुके हैं। ऐसे में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है।



अभिभावकों में भी बढ़ी चिंता

विश्वविद्यालय परिसर में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों की चिंता भी बढ़ा दी है। जिस परिसर में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं, वहां बाहरी युवकों के घुसकर हथियार से हमला करने की घटना विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। छात्रों का कहना है कि पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने से विश्वविद्यालय की छवि भी प्रभावित हो रही है।

छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

मथुरा में कार और ट्रैक्टर टकराने पर दो पक्ष भिड़े

भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष पर टीएसआई से मारपीट का आरोप, 3 पर एफआईआर

तमसा संकेत, एजेंसी



मथुरा। मथुरा के मंडी चौराहे पर रविवार रात कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर के बाद हंगामा हो गया। आरोप है कि भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा के पति देवाशीष शर्मा ने ट्रैक्टर चालक से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे यातायात पुलिस के TSI राकेश कुमार के साथ भी मारपीट की गई। इससे वह सड़क पर गिर गए। हंगामे के कारण चौराहे पर जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक, रविवार रात करीब 9 बजे मधु शर्मा अपने पति देवाशीष शर्मा और बेटे के साथ कार से मंडी चौराहे से गुजर रही थीं। इसी दौरान उनकी कार ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर देवाशीष शर्मा कार से डंडा निकाल लाए और ट्रैक्टर चालक से मारपीट करने लगे। हंगामा देखकर ड्यूटी पर तैनात TSI राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान देवाशीष शर्मा ने TSI से भी अभद्रता और मारपीट की। इससे TSI सड़क पर गिर गए। इसके बाद लोगों की मदद से मामला शांत कराया गया और पुलिस ने जाम खुलवाया। TSI ने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि TSI की तहरीर पर कोतवाली में मधु शर्मा, उनके पति और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, देवाशीष शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि ट्रैक्टर चालक ने उनकी कार में टक्कर मारी थी और मना करने के बाद भी कार को रगड़ते हुए निकल रहा था। उन्होंने TSI से मारपीट करने से भी इनकार किया। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की, जिससे उनके हाथ में चोट लगी।

'2027 में पीडीए की बनेगी सरकार'

अलीगढ़ में सपा प्रवक्ता सोमैया राणा बोलीं- वोट, खाद और चंदा चोरी से लोग गुस्से में हैं

तमसा संकेत, एजेंसी



कोल। समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सोमैया राणा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक अधिकारों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान एवं न्याय पहुंचाने की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ा रही है। राणा ने दावा किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ देश की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिलेगा और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की सरकार बनेगी। सोमैया राणा ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपना स्थापना दिवस केवल संगठन के कार्यक्रम के तौर पर नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश के साथ मना रही है। उनके मुताबिक पार्टी का उद्देश्य समाज के उन वर्गों की आवाज को मजबूती देना है, जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सम्मान नहीं मिलने का दावा किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सपा अपने राजनीतिक संघर्ष को सामाजिक न्याय के मुद्दे से जोड़कर आगे बढ़ा रही है। सपा प्रवक्ता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए 'वोट चोरी', 'खाद चोरी' और 'चंदा चोरी' जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने दावा किया कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच नाराजगी है। राणा ने कहा कि किसान, युवा और आम नागरिकों से जुड़े सवालों को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी लोगों में असंतोष है। राणा के मुताबिक, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता से जुड़े ये मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इन्हीं सवालों को लेकर जनता के बीच अपनी बात पहुंचा रही है और सामाजिक न्याय को अपने राजनीतिक एजेंडे का प्रमुख आधार बना रही है। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीडीए को अपनी राजनीतिक रणनीति का प्रमुख आधार बताती रही है। पार्टी की ओर से पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग बताया जाता है। सोमैया राणा ने भाजपा के एक सांसद की कथित महिला विरोधी टिप्पणी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कथित टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए न्यायालय से मामले का स्वतः संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की। राणा ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति की ओर से महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी किए जाने पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सपा प्रवक्ता ने न्यायपालिका से इस तरह के मामलों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। सोमैया राणा ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पीडीए के साथ आगे बढ़ रही है और समाज के अलग-अलग वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। राणा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक बराबरी, सम्मान और अधिकारों के सवालों से भी जुड़ा हुआ है।

पृष्ठ 01 का शेष...

'चुनाव आयोग ने ...

दोनों याचिकाओं में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR से जुड़े कदमों को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। मामले में CEC को निलंबित करने की मांग के बीच यह सवाल भी अहम है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे निलंबित करने की विशेष शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनावों के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि, चुनाव आयोग के फैसलों की न्यायिक समीक्षा संभव है। यदि किसी निर्णय में कानून या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो अदालत उसके खिलाफ उचित आदेश दे सकती है। सोमवार की सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले संबंधित पक्षों का जवाब लेने और रिकॉर्ड की जांच करने पर जोर दिया।

बाढ़ प्रभावितों के...

अगर तटबंध बन जाए तो हमारी पीढ़ियों के लिए भी मदद मिल जाएगी। मैकूलाल को भी राहत सामग्री मिली है। उन्होंने बताया- हमारे लिए राशन मिला है। पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा। भूसा के साथ चोकर भी देने को कहा है। सीएम योगी ने जिन लोगों से बात की, उनसे रिपोर्टर आशुतोष द्विवेदी ने हाल जाना।लल्ला ने कहा- मुख्यमंत्री ने बातचीत की और पूछा कि तुम्हारे घर में पानी है। उनका हालचाल पूछना देखकर अच्छा लगा। राहत सामग्री दी है, जो अच्छी बात है। सीएम योगी ने कहा- इस आपदा की घड़ी में डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। आज राहत सामग्री दी गई है। आगे भी राहत सामग्री दी जाती रहेगी। आपके साथ आपका जो महत्वपूर्ण धन है- पशुधन, उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है। हमारे विधायक, बीजेपी के जिलाध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष आदि आपकी मदद में लगे हुए हैं। मैं यही कहने आया हूं कि सरकार इस घड़ी में आपके साथ खड़ी है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें यही कामना है। यही कोशिश है। सीएम योगी ने कहा- खुले के बजाय स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था की जाए, ऐसा मैंने प्रशासन से कहा है। स्कूलों में रुकने से खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। गर्भवतियों के लिए पोषाहार उपलब्ध कराए जाएंगे। पशुओं के चारे के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। केवल सूखा भूसा नहीं, बल्कि चोकर आदि भी उपलब्ध कराया जाए। सीएम योगी ने कहा- फैजुल्लागंज से नैमिषनगर तक तटबंध बनेगा। तटबंध पर चलने की व्यवस्था भी बनेगी। यानी वह तटबंध सुरक्षा करेगा, साथ ही सुविधा भी देगा। सीएम योगी ने कहा- हर प्रभावित को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो, 2 किलो अरहर की दाल, बरसाती, बाल्टी, नमक, लाई-भूंजा आदि बांट रहे हैं। पशुओं के चारे के लिए भी निर्देश दिए हैं। मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की जा रही है। मिल्लत नगर में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे लोग सड़क पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी मिल्लतनगर की ओर नहीं आ रहे हैं। घरों में किसी के न होने से चोरियां हो रही है। उनका कहना है कि हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। लोग अपने घरों से जरूरी सामानों को लेकर जा रहे हैं। महिलाएं घुटने भर पानी में होकर अपने परिवार के साथ निकल रही है। महिलाओं ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि पानी कम हो जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी पानी बढ़ रहा है। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से फैजुल्लागंज के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति को रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने गंभीरता से लिया। सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी के मुताबिक, राजनाथ सिंह ने डीएम से फोन पर बात कर प्रभावित इलाकों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने राहत-बचाव कार्य प्राथमिकता से चलाने और जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी फोन पर बात की। दोनों के बीच फैजुल्लागंज समेत गोमती के आसपास के प्रभावित इलाकों और प्रस्तावित बांध-पुल को लेकर चर्चा हुई। पार्टी पदाधिकारियों ने क्षेत्र की समस्या पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए रक्षा मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटौंजा में करीब 300 बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहत सामग्री पाने वाले प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है।

अपराधियों में मौत का ...

इसके बाद दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 4 अगस्त से 21 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा-दिल्ली बस, आस्था कुंज पार्क और स्वरूप नगर में रेप की 3 घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले में पहली सुनवाई 28 सितंबर को हुई थी। 4 अगस्तः दिल्ली में 16 साल की नाबालिग से चलती बस में गैंगरेप। पीड़ित ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में बैठी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर छोड़ा। इस दौरान बस करीब 47 किमी दौड़ती रही। बस के शीशों पर पर्दे लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि सार्वजनिक जगहों को खराब रोशनी, निगरानी की कमी और पेट्रोलिंग की कमी जैसी वजहों से 'हाई रिस्क जोन' नहीं बनने दिया जा सकता। सिर्फ संवेदना जताना समाधान नहीं है, बल्कि अपराध रोकने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आस्था कुंज पार्क की घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि LSR कॉलेज की छात्राओं ने पहले भी यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं किए गए।

सोने की सिल्ली में ...

उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों को 'हाता नहीं भाता', इन्होंने एक युवा विधवा को जेल में तड़पाया और प्रोफेसर, पत्रकार व ईमानदार अधिकारी तक को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरिडोर, पुल, एक्सप्रेस-वे और मंदिर के नाम पर पैसे खाने वाले, अपने सत्ता-सजातीयों को हर अपराध के बाद बचाने वाले और जनता के टैक्स के 2.5 करोड़ रुपये हर दिन अपनी नकली छवि बनाने पर लुटाने वाले भाजपाइयों पर जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। उन्होंने विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगवाने, विरोधियों के फेक एनकाउंटर करवाने, बुलडोजर से घर गिरवाने और स्कूल बंद करवाने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि उनके अपने विधायक तक विरोध कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के पैसे सोने की सिल्ली में ढलवाए जा रहे हैं। अखिलेश ने कमरतोड़ महंगाई, प्रशासनिक अक्षमता, बिजली-पानी-सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी, किसानों को फसल का सही दाम न मिलना, खाद-सिंचाई-बिजली की समस्या, छुट्टा पशुओं से खेती का नुकसान और व्यापार-कारोबार को दूसरे राज्यों के ठेकेदारों को नीलाम करने का जिक्र किया।

यूपी में भाजपा के ...

मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, बृजलाल, गीता शाक्य, अरुण सिंह को दोबारा मौका नहीं मिला है। यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इनमें 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। 6 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है।

भाजपा से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा और नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, बृजलाल, गीता शाक्य, अरुण सिंह और सपा के रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी गौतम का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है।डॉ. दिनेश शर्मा अंडमान निकोबार बना दिए गए हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है।सपा के 2 उम्मीदवार प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नाथवानी ने 30 सितंबर को नामांकन दाखिल किया है।सपा तीसरे और भाजपा 9वें उम्मीदवार को नहीं उतारती है तो चुनाव में सपा के 2 और भाजपा के 8 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है।

फरवरी में शादी हुई थी, पूजा के बाद बोले- व्यवस्थाओं से खुश हूं, स्वामी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया

शिखर धवन पत्नी सोफी शाइन संग तिरुमला पहुंचे

धवन की पहली शादी आएशा मुखर्जी से हुई थी। दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम जोरावर है।
आठ साल की शादी के बाद दोनों अक्टूबर 2023 में अलग हो गए थे। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को तलाक कंफर्म किया था।
धवन ने कहा है कि शादी खत्म होने के बाद वह करीब दो साल से अपने बेटे जोरावर से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाए हैं।

प्रशंसा

नई दिल्ली, एजेंसी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन सोमवार को पत्नी सोफी शाइन के साथ तिरुमला मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में धवन और सोफी पारंपरिक कपड़ों में मंदिर पहुंचे। धवन ने भक्तों से मुलाकात की और फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचाईं। धवन और सोफी ने 21 फरवरी 2026 को शादी की थी।



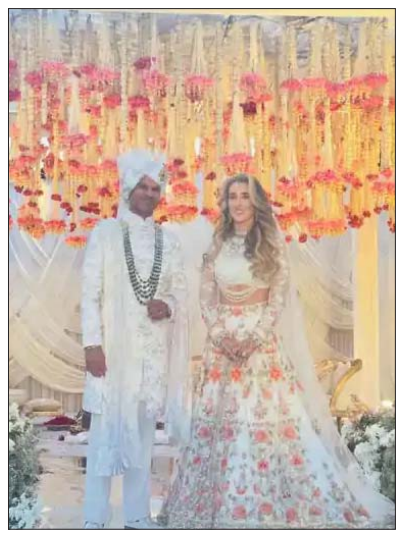
शिखर धवन ने 2010 में टी-20 और 2011 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया। हालांकि, टीम में जगह बनाने में उन्हें 3 साल लग गए। 2013 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, यहीं से वे तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए। उन्होंने 10 दिसंबर 2022 तक भारत के लिए 167 वनडे, 68 टी-20 और 34 टेस्ट खेले। इनमें 24 शतक और 55 फिफ्टी शामिल रहीं। धवन ने 24 अगस्त 2024 को इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली हैं। जब वह धवन से मिली थी तब UAE में जॉब करती थी। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉरपोरेशन में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट (प्रोडक्ट कंसल्टेंट) के पद पर कार्यरत रही हैं। सोफी पिछले साल जुलाई से धवन की स्पोर्ट्स कंपनी डा वन स्पोर्ट्स की COO (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) हैं।

उन्होंने आयरलैंड के लिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कैसलरॉय कॉलेज से पूरी की। सोफी, धवन के इंस्टाग्राम पर आने वाले कई मजेदार वीडियो में भी नजर आती रहती हैं।

व्यवस्थाओं की तारीफ की

दर्शन के बाद धवन ने मीडिया से कहा कि मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थीं। उन्होंने भगवान तिरुपति के अच्छे दर्शन के लिए आभार जताया। धवन ने कुर्ता और धोती पहनी थी। सोफी सफेद सूट में नजर आईं।

दर्शन के बाद धवन ने कहा, मेरा दर्शन बहुत शानदार रहा। यहां प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थीं। भगवान तिरुपति के इतने अच्छे दर्शन पाकर मैं बहुत आभारी हूं।



धवन और सोफी शाइन ने 21 फरवरी 2026 को शादी की थी।

सूर्यकुमार यादव रणजी ट्रॉफी में लौटेंगे

मुंबई के लिए 11 अक्टूबर से खेल सकते हैं

नई दिल्ली, एजेंसी

पूर्व भारतीय टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 2026-27 रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलने के लिए उपलब्ध हैं। वे मुंबई के पहले एलीट ग्रुप D मैच में चंडीगढ़ के खिलाफ खेल सकते हैं।

मुंबई और चंडीगढ़ के बीच यह मुकाबला 11 अक्टूबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। सूर्यकुमार ने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच IPL 2026 में खेला था।

वहीं, पूर्व मुंबई कप्तान शार्दूल ठाकुर हाथ की चोट के कारण शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे। उनकी गैरमौजूदगी में तुषार देशपांडे मुंबई के तेज गेंदबाजी अटैक की अगुआई करेंगे।

सूर्यकुमार ने फरवरी 2025 में नागपुर में विदर्भ के खिलाफ मुंबई के लिए आखिरी रणजी मैच खेला था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उन्होंने घरेलू रेड-बॉल टूर्नामेंट के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, सूर्या ने MCA अध्यक्ष अजिंक्य नाइक को आगामी रणजी ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि की है। सूर्यकुमार ने अब तक 86 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं। उनके नाम 5,758 रन हैं। उन्होंने 144 पारियों में 14 शतक और 30 अर्धशतक लगाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 42.33 है।



वेस्टइंडीज टीम ने मांगा एक्स्ट्रा नारियल पानी

इंदौर, एजेंसी

इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टी-20 मुकाबले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों की डाइट, हाइड्रेशन और रिकवरी का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी बीच वेस्टइंडीज टीम ने इंदौर में नारियल पानी का एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की विशेष मांग की है।



वेस्टइंडीज टीम के मैनेजर ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) से फोन पर एक्स्ट्रा नारियल पानी उपलब्ध रखने का आग्रह किया है। MPCA के सीईओ रोहित पंडित के मुताबिक, खिलाड़ियों के लिए सामान्य तौर पर नारियल पानी की व्यवस्था रहती है, लेकिन इस बार वेस्टइंडीज टीम ने इसकी अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इंदौर में बारिश के बाद अब तापमान बढ़ने के साथ गर्मी और ड्राई हीट का असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैदान पर लगातार दौड़ने, फील्डिंग और बल्लेबाजी-गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ियों के लिए हाइड्रेशन अहम है। टीम प्रबंधन चाहता है कि खिलाड़ियों को जरूरत के समय नारियल पानी आसानी से उपलब्ध हो।

दोनों टीमों के खिलाड़ियों की पसंद और जरूरत के अनुसार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। डाइट में वेजेटेरियन विकल्प ज्यादा रखे गए हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और मैच के बाद रिकवरी को ध्यान में रखते हुए खान-पान तैयार किया जाएगा।

इंदौर में 11 अक्टूबर को भारत से टी-20 मुकाबला
डिहाइड्रेशन से बचने शाकाहारी भोजन पर जोर

प्रज्ञान चुन सकते हैं न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम

लंदन। न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान इस हफ्ते हो सकता है। प्रज्ञान ओझा 5 से 11 अक्टूबर के बीच होने वाली सिलेक्शन मीटिंग की अगुवाई करेंगे। वे सितंबर 2025 में टीम इंडिया के सिलेक्टर बने थे। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है। BCCI ने अभी तक उनका उत्तराधिकारी तय नहीं किया है। न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा। वहां टीम इंडिया को पांच T20Is, पांच ODIs और दो टेस्ट खेलने हैं। नए चयनकर्ता की नियुक्ति तक समिति चार सदस्यों के साथ काम करेगी। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रज्ञान ओझा अगरकर के बाद पहली चयन बैठक की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे अंतरिम तौर पर चयन समिति के प्रमुख की भूमिका में होंगे। हालांकि, यह साफ नहीं है कि उनकी भूमिका अस्थायी होगी या स्थायी। BCCI की पांच सदस्यीय चयन समिति में नए चयनकर्ता की नियुक्ति तक चार सदस्य रहेंगे।

भारत पर 20%, वेस्टइंडीज पर 10% मैच फीस का जुर्माना, दोनों कप्तानों ने गलती मानी

न्यू चंडीगढ़ वनडे में स्लो ओवर रेट पर आईसीसी की कार्रवाई

आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के प्रकाश भट्ट ने दोनों टीमों पर जुर्माना लगाया। दोनों कप्तानों ने आरोप स्वीकार कर प्रस्तावित सजा मान ली। इसलिए मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

नई दिल्ली, एजेंसी

न्यू चंडीगढ़ में शनिवार को भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में स्लो ओवर-रेट के लिए ICC ने दोनों टीमों पर जुर्माना लगाया है।

भारतीय खिलाड़ियों की मैच फीस का 20% और वेस्टइंडीज खिलाड़ियों की मैच फीस का 10% काटा जाएगा। टाइम अलाउंस को ध्यान में रखने के बाद भारत 4 ओवर और वेस्टइंडीज 2 ओवर पीछे रही। स्लो ओवर-रेट के चार्ज ऑन-फील्ड अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगाज्स्की ने लगाए। थर्ड अंपायर शराफुद्दौला इब्ने शाहिद और फोर्थ अंपायर वीरेंद्र शर्मा भी चार्ज लगाने की प्रक्रिया में शामिल थे। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप की नाबाद 162 रन की पारी के दम पर 48.2 ओवर में 5 विकेट पर 352 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि, भारत ने पहले दो मैच जीतकर 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की।



तीसरे वनडे में टॉस के दौरान शुभमन गिल और शाई होप हाथ मिलाते हुए।

आईसीसी के नियम 2.22 के तहत कार्रवाई

ICC के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के मुताबिक, तय समय में ओवर पूरे नहीं करने पर हर कम ओवर के लिए खिलाड़ियों की मैच फीस का 5% जुर्माना लगाया जाता है। इसी नियम के तहत भारत पर 4 ओवर कम करने के लिए 20% और वेस्टइंडीज पर 2 ओवर कम करने के लिए 10% जुर्माना लगाया गया।

मनोरंजन

डीपफेक वीडियो पर भड़कीं जान्हवी कपूर जूनियर एनटीआर और चिरंजीवी का जताया आभार

तकनीक का गलत इस्तेमाल यौन उत्पीड़न जैसा : जान्हवी

नई दिल्ली, एजेंसी

अभिनेत्री जान्हवी कपूर ने अपनी फिल्म 'देवराः पार्ट 1' के गाने 'चुट्टामल्ले' पर बने AI जनरेटेड अश्लील (डीपफेक) वीडियो पर कड़ी नाराजगी जताई है।

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक बयान जारी कर उन्होंने तकनीक के इस गलत इस्तेमाल को यौन उत्पीड़न के बराबर बताया। जान्हवी ने कहा कि बिना मर्जी के महिलाओं का ऐसा कंटेंट बनाना उनकी गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बोलने और समर्थन देने के लिए अपने को-स्टार जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी, विजय देवरकोंडा और खुशबू का आभार व्यक्त किया। एक्ट्रेस ने महिलाओं की पसंद और उनके शरीर के प्रति सम्मान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला पांच दिन 'हां' कहती है और छठे दिन 'ना', तो उस 'ना' का सम्मान किया जाना चाहिए। मिनीस्कर्ट पहनने का मतलब यह नहीं होता कि कोई उसके नीचे कैमरा लगाए या उसके शरीर का गलत इस्तेमाल करे। महिला किस चीज में सहज है और अपनी सीमा कहां तय करती है, यह फैसला पूरी तरह से उसी का होना चाहिए।



जूनियर एनटीआर ने मॉर्फ्ड 'चुट्टामल्ले' वीडियो बनाने और उसे फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा कि 'चुट्टामल्ले' के इस मॉर्फ्ड वीडियो को बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ मैं हर संभव कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।



जान्हवी कपूर ने फिल्म 'देवरा : पार्ट 1' से बतौर लीड एक्ट्रेस साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था।

टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल यौन उत्पीड़न जैसा

जान्हवी कपूर ने अपने बयान में लिखा कि महिलाओं को केवल एक वस्तु की तरह दिखाना और उनकी सहमति के बिना एडिटेड कंटेंट फैलाना बेहद गंभीर मामला है। यह आपराधिक कृत्य लगभग यौन उत्पीड़न के ही समान है। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की लगभग हर महिला ने किसी न किसी रूप में इस परेशानी का सामना किया है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह आम महिलाएं भी इसका शिकार हो रही हैं।

'अपनी बेटियों को बचाओ' की जगह सोच बदलने की जरूरत

जान्हवी ने आगे कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर महिलाओं को सीमाओं के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सलाह दी कि लोगों को सिर्फ अपनी बेटियों की सुरक्षा करने की बात कहने के बजाय अपनी सोच बदलनी होगी। समाज को ऐसी मानसिकता विकसित करने की जरूरत है जो लोगों को दूसरों की प्राइवेसी और सीमाओं का उल्लंघन करने से रोके।



गोविंदा की बेटी टीना ने कोमल रानी पर सवाल टाला

कहा- सिर्फ इवेंट पर बात करें, कोमल का आरोप- सुनीता ने गोविंदा को बर्बाद किया

नई दिल्ली, एजेंसी

सुनीता आहूजा और कोमल रानी के बीच चल रहे विवाद पर गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

कोमल रानी के मां सुनीता आहूजा पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच, जब एक इवेंट में मीडिया ने टीना से इस बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने मामले से दूरी बना ली और बिना जवाब दिए वहां से चली गईं।

इवेंट के दौरान टीना से मीडिया ने पूछा, ₹कोमल रानी इंस्टाग्राम पर आपकी मम्मी सुनीता आहूजा पर कई आरोप लगा रही हैं।

इस सवाल को सुनते ही टीना ने तुरंत इसे टाल दिया और कहा, ₹प्लीज हम यहां सिर्फ इवेंट के बारे में बात करते हैं... धन्यवाद₹। इतना कहने के बाद वे पैपराजी के बीच से आगे बढ़ गईं और बात आगे नहीं बढ़ाई।



यह पूरा मामला तब गरमाया जब कोमल रानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर कर सुनीता आहूजा पर तीखे आरोप लगाए। कोमल ने लिखा, ₹जो औरत सालों से अपने ही पति की जान लेने की कोशिश कर रही हो, ऐसी औरतों की बदुआएं किसी को नहीं लगतीं।

उन्होंने आगे कहा कि जो घर पहले से टूटा हुआ हो, उसे कोई और नहीं तोड़ सकता। कोमल ने सवाल उठाया कि क्या यह सच में दर्द है या फिर लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए रची गई कोई सोची-समझी साजिश है।

कोमल ने अपने पोस्ट में सुनीता पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि किसी इंसान को लगातार मानसिक रूप से परेशान करना, काम करने से रोकना, घर पर बैठने और बर्बाद होने के लिए मजबूर करना तथा पूरी तरह अलग-थलग कर देना किसी अच्छी पत्नी का बर्ताव नहीं हो सकता।

उन्होंने आरोप लगाया कि सुनीता बंद कमरों के पीछे का काम सार्वजनिक रूप से कर रही हैं और अपील की कि वे अपने एजेंडे के लिए उनके नाम का इस्तेमाल बंद करें।

बोले- कैप्टन स्मित पर चुप क्यों, एलपीयू की घटना पर क्यों नहीं बोल रहे, सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे नसीरुद्दीन

नसीरुद्दीन शाह पर पीयूष मिश्रा का तंज

मुंबई, एजेंसी

मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट में एक्टर नसीरुद्दीन शाह और संगीतकार विशाल ददलानी समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। इसी बीच एक्टर पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह की अभिजीत दिपके से मुलाकात का जिक्र करते हुए देश के अन्य मुद्दों पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए।

उन्होंने दुबई की फ्लाइट में 170 यात्रियों की जान बचाने वाले स्मिथ मच्छर की तारीफ करने और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) की घटना पर बयान देने की मांग की।

पीयूष ने देश के अन्य मुद्दों पर नसीरुद्दीन शाह की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब नसीर साहब के हर बयान का वे खुद जवाब देंगे। पीयूष ने पूछा कि ये बच्चे कब से एक्टिंग टीचर हो गए, नसीर साहब को इस पर भी मैसेज भेजकर अपनी संवेदना जतानी चाहिए। वीडियो में पीयूष मिश्रा ने झारखंड छात्र आंदोलन के दौरान मांगी गई मदद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने झारखंड के लिए नसीर साहब से मदद मांगी थी, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी शायरा की नज्म भेज दी थी। पीयूष ने कहा कि वहां के लोगों को किसी शायरा की नज्म नहीं, बल्कि आटा, दाल, रोटी, लिट्टी और चोखा चाहिए था। उन्हें कोई पिज्जा या बर्गर नहीं चाहिए था। पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह को साफ शब्दों में कहा कि अब वे जब भी कोई सार्वजनिक बयान देंगे, तो उन्हें पीयूष मिश्रा की तरफ से जवाब जरूर मिलेगा। उन्होंने खुद को नसीर साहब का पुराना जानकार बताते हुए 'इंकलाब जिंदाबाद' के साथ अपनी बात खत्म की।





पीयूष मिश्रा ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि वहां छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई के दौरान धक्का-मुक्की और हंगामा हुआ।
पीयूष ने तंज कसते हुए याद दिलाया कि नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि उन्होंने जितना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एफटीआईआई में नहीं सीखा, उतना इन बच्चों से सीखा है।

'फ्लाइट हादसे में जान बचाने वाले की तारीफ करें'

पीयूष मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया वीडियो में नसीरुद्दीन शाह से कहा कि वे पुराने जानकार हैं। पीयूष ने हाल ही में फ्लाईदुबई की फ्लाइट 1073 में टले हादसे का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि स्मित मच्छार नाम के व्यक्ति ने बहादुरी दिखाकर 170 लोगों की जान बचाई है। नसीर साहब को उस घटना पर भी कमेंट करना चाहिए और उस जांबाज को बधाइयां देनी चाहिए।

मेडिसिन का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिला

पुरस्कृत रोशनी से दिमाग की नसों को नियंत्रित करने का तरीका खोजा

नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी थॉमस पर्लमैन इस साल के फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार के विजेता का ऐलान करेंगे। पुरस्कार की घोषणा से कुछ ही पल पहले नोबेल कमेटी ने इसकी जानकारी दी है।



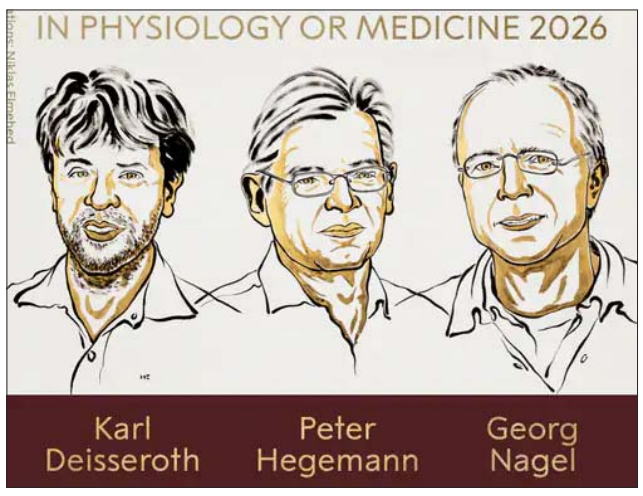
तस्वीर नोबेल कमेटी के सेक्रेटरी थॉमस पर्लमैन की है।

स्टॉकहोम, एजेंसी

2026 का नोबेल मेडिसिन पुरस्कार ऑप्टोजेनेटिक्स नाम की तकनीक के लिए पीटर हेगेमैन, जॉर्ज नागेल और कार्ल डीसेरोथ को दिया गया है।

इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक दिमाग की नसों यानी तंत्रिका कोशिकाओं को रोशनी से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा दिमाग यादों, भावनाओं और व्यवहार को कैसे कंट्रोल करता है।

स्वेतलाना मोइसोव ने GLP-1 हार्मोन के उस हिस्से की पहचान करने में अहम भूमिका निभाई, जो शरीर पर सबसे ज्यादा असर करता है। GLP-1 भूख और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। उनकी रिसर्च ने आगे चलकर मोटापा और डायबिटीज की



दवाओं का रास्ता खोला। इस काम में डैनियल ड्रकर और जेन्स जूल होल्स्ट का भी अहम योगदान रहा।

डैनियल ड्रकर ने GLP-1 के शरीर पर असर को समझने में अहम योगदान दिया। उनकी रिसर्च से पता चला कि यह हार्मोन इंसुलिन, ब्लड शुगर और भूख को कैसे प्रभावित करता है। उनके काम ने GLP-1 आधारित दवाओं को डायबिटीज और मोटापे के इलाज तक पहुंचाने में मदद की।

रोशनी को महसूस करने वाले प्रोटीन की खोज

वैज्ञानिक पीटर हेगेमैन यह समझना चाहते थे कि यह शैवाल रोशनी की तरफ कैसे तैरती है। इसी सवाल पर काम करते हुए उन्होंने और जॉर्ज नागेल ने शैवाल में एक खास प्रोटीन की पहचान की। इसका नाम चैनलरोडोप्सिन है।

आसान भाषा में कहें तो यह प्रोटीन कोशिका के लिए रोशनी को महसूस करने वाले सेंसर की तरह काम करता है।

जब इस प्रोटीन पर नीली रोशनी पड़ती है, तो इसमें एक छोटा रास्ता खुल जाता है। इस रास्ते से विद्युत आवेश वाले छोटे कण कोशिका के अंदर जाने लगते हैं। इससे कोशिका में एक विद्युत संकेत पैदा होता है।

वैज्ञानिकों ने आगे इसका प्रयोग दूसरी कोशिकाओं पर किया। उन्होंने चैनलरोडोप्सिन को दूसरी कोशिकाओं में डालकर देखा। इसके बाद ये कोशिकाएं भी रोशनी पड़ने पर विद्युत संकेत पैदा करने लगीं। यहीं से वैज्ञानिकों को यह समझ आया कि इस प्रोटीन की मदद से रोशनी के जरिए कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है।

डेविड लियू ने जीन एडिटिंग की ऐसी तकनीकें विकसित कीं, जिनसे DNA में खास हिस्सों को ज्यादा सटीक तरीके से बदला जा सकता है। उनकी बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीकों का इस्तेमाल आनुवंशिक बीमारियों के इलाज की दिशा में किया जा रहा है। उनका नाम मेडिसिन के साथ 2026 केमिस्ट्री नोबेल की चर्चाओं में भी है।

डेनिस स्लैमोन ने स्तन कैंसर में HER2 जीन की भूमिका समझने में अहम काम किया। उनकी रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल से हर्सेप्टिन जैसी लक्षित दवा के विकास का रास्ता खुला। यह दवा HER2-पॉजिटिव स्तन कैंसर के इलाज में बड़ा बदलाव लेकर आई। टिमोथी स्प्रिंगर ने यह समझने में अहम योगदान दिया कि प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं एक-दूसरे को कैसे पहचानती और जोड़ती हैं। उनकी रिसर्च से ऐसी दवाओं के विकास में मदद मिली, जिनका इस्तेमाल ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में होता है।

फास्ट न्यूज

अमेरिका-भारत ट्रेड डील की बातचीत में अब ज्यादा गुंजाइश नहीं

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत ऐसी जगह पर आकर अटक गई है, जहां से आगे बढ़ना दोनों देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित 'म्यूनिख लीडर्स मीटिंग' के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बात उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां न तो भारत और छूट देने को तैयार है, और न ही अमेरिका।

आज सोने के दाम में 353 की गिरावट

नई दिल्ली। सोने के दाम में आज यानी 5 अक्टूबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 353 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं एक किलो चांदी 2,105 रुपए महंगी होकर 2.23 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले बीते महीने यानी सितंबर में सोना 8 हजार और चांदी 15 हजार सस्ती रुपए हुई। 31 अगस्त को सोना 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था जो 30 सितंबर को 1.48 लाख रुपए पर आ गया। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत 2.37 लाख रुपए से गिरकर 2.20 लाख रुपए पर आ

टैक्स अधिकारियों से छिनेगा गिरफ्तारी का अधिकार

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल 7 अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक में देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकती है। नए प्रस्ताव के तहत टैक्स अधिकारियों से सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार वापस लेने और फर्जीवाड़े के आपराधिक मामलों की सीमा बढ़ाने की तैयारी है।

ट्रम्प के कामकाज से 70% अमेरिकी संतुष्ट नहीं

न्यूयॉर्क, एजेंसी



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी में बगावत के संकेत दिखने लगे हैं। ट्रम्प की लोकप्रियता घट रही है। पार्टी नेताओं को डर है कि मिडटर्म चुनाव में ट्रम्प का साथ उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले कई रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रम्प से दूरी बना रहे हैं। कुछ ने अपनी चुनावी वेबसाइट से ट्रम्प और उनके 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे का जिक्र हटा दिया है। कुछ नेता उनके साथ मंच साझा करने से भी बच रहे हैं। AP-NORC सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 30% अमेरिकी ट्रम्प के कामकाज से खुश हैं। अर्थव्यवस्था पर उनकी अप्रूवल रेटिंग 26% है। महंगाई से निपटने के मामले में यह सिर्फ 17% है। 65% से ज्यादा अमेरिकी बढ़ती कीमतों के लिए ट्रम्प की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं।

आयोवा से सांसद और सीनेट उम्मीदवार एश्ले हिंसन और मिशिगन के सीनेट उम्मीदवार माइक रोजर्स ने ईरान युद्ध जल्द खत्म करने की मांग की है। दोनों पहले ट्रम्प की सैन्य कार्रवाई के समर्थक थे। आयोवा के सांसद जैक नन और मैरियानेट मिलर-मीक्स ने ट्रम्प की युद्ध शक्तियां सीमित करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ वोट किया। फ्लोरिडा की सांसद मारिया ने ट्रम्प की सख्त इमिग्रेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। कई उम्मीदवारों ने कहा है कि वे ट्रम्प का प्रचार नहीं चाहते।

रिपब्लिकन उम्मीदवारों की बेचैनी के पीछे सबसे बड़ा कारण अर्थव्यवस्था है।

ताइवानी राष्ट्रपति के बेटे का वीडियो बनाया, चीन जाते समय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

चीन के लिए जासूसी के शक में अमेरिकी महिला गिरफ्तार

जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों ने घर और वहां आने वाले लोगों की तस्वीरें और वीडियो बनाए। पड़ोसी के सुरक्षा कैमरे की फुटेज में भी दोनों को कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए देखा गया था।



वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने रविवार को लॉस एंजिल्स एयरपोर्ट से 34 साल की एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला पर आरोप है कि उसने चीन सरकार के लिए काम करते हुए ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के बेटे की निगरानी की और उसकी तस्वीरें व वीडियो चीन तक पहुंचाए। अमेरिकी महिला की पहचान वैनयिंग झांग उर्फ हीदर झांग के रूप में हुई है। वह कैलिफोर्निया के इरविन शहर में रियल एस्टेट एजेंट है। FBI ने उसे उस समय गिरफ्तार किया, जब वह लॉस एंजिल्स से शंघाई जाने वाली फ्लाइट पकड़ने वाली थी। अमेरिकी अधिकारियों ने उस पर किसी विदेशी सरकार के लिए काम करने का आरोप



लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, झांग ने इस दौरान चीन के एक सरकारी अधिकारी को वीचैट पर जानकारी भेजी। FBI के मुताबिक, उसने बताया कि उसने टिंग-यू को देख लिया है और उसका वीडियो बना रही है। उसने दो गाड़ियों के नंबर भी भेजे थे। जांच एजेंसी का कहना है कि इसके बाद झांग ने मैसेज भेजकर कहा था कि वह यह काम संभाल लेगी।

कुछ समय बाद उसने अधिकारी को बताया कि वह अगले हफ्ते सिएटल जा सकती है। इसके बाद ही सितंबर 2025 में वह अपने साथी के साथ सिएटल गई और राष्ट्रपति के बेटे के घर की निगरानी की। FBI एजेंट होल्ट ने शिकायत में कहा कि अगर चीन किसी संभावित संघर्ष के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति पर दबाव बनाना चाहता है, तो उनके करीबी रिश्तेदारों की लोकेशन, घर और गाड़ियों की तस्वीरें उसके लिए उपयोगी हो सकती हैं।

जून में चीनी अधिकारी से मिलने गई थी महिला

FBI की शिकायत के मुताबिक, इस पूरे मामले की शुरुआत जून 2025 में हुई थी। झांग को उसकी पुरानी यूनिवर्सिटी के एक दोस्त ने चीन के एक सरकारी अधिकारी से मिलवाया था। झांग जून में चीन के चांगशा शहर गई थी। वहां उसने एक निजी कमरा बुक किया, जहां उसकी चीनी अधिकारी से मुलाकात हुई। FBI के मुताबिक, अधिकारी ने उसे निगरानी से जुड़ा काम दिया था।

कैलिफोर्निया में रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करती थी

गिरफ्तार महिला की पहचान वैनयिंग हीदर झांग (34) के रूप में हुई है। वह कैलिफोर्निया के इरविन में रियल एस्टेट एजेंट है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, झांग सितंबर 2025 में एक और व्यक्ति के साथ लास वेगास से सिएटल गई थी। दोनों ने वहां एक काली निसान रोग कार किराए पर ली और ताइवान के राष्ट्रपति के बेटे टिंग-यू लाई के घर के पास पहुंचे।

ब्राजील में राष्ट्रपति लूला हार सकते हैं चुनाव

ट्रम्प के करीबी फ्लाविया बोल्सेनारो पहले दौर में आगे, पिता 27 साल जेल की सजा काट रहे

ब्रासीलिया, एजेंसी



ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा चुनाव हार सकते हैं। 4 अक्टूबर को ब्राजील में पहले दौर की वोटिंग हुई। इसमें राष्ट्रपति लूला, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे से पिछड़ गए।

किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, इसलिए अब ब्राजील में 25 अक्टूबर को दूसरे दौर की वोटिंग होगी।

बोल्सोनारो परिवार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का करीबी माना जाता है। 2022 का चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की साजिश के मामले में जायर बोल्सोनारो को करीब 27 साल की जेल की सजा मिली है।

चुनाव से पहले आए ज्यादातर सर्वे लूला को बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन नतीजों ने तस्वीर बदल दी।

पहले दौर में लूला और फ्लाविया के अलावा 10 और उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। वे चुनाव से बाहर हो गए हैं, लेकिन उन्हें मिले वोट अब भी बहुत मायने रखते हैं। दूसरे दौर में इन्हीं वोटों से तय हो सकता है कि लूला या फ्लाविया में से कौन राष्ट्रपति बनेगा। इनमें रोनाल्डो काइआडो और रेनान सैंटोस के वोट सबसे ज्यादा अहम हैं। दोनों को मिलाकर करीब 53 लाख वोट मिले हैं। अभी दोनों ने यह नहीं बताया है कि वे लूला का साथ देंगे या फ्लाविया का। एक और बड़ी बात यह है कि पहले दौर में करीब 21% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। अब दूसरे दौर में यह देखना होगा कि इनमें से कितने लोग वोट डालने आते हैं और किसे वोट देते हैं। 80 साल के लूला दा सिल्वा चौथी बार ब्राजील की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चुनावी दांव गरीबों के लिए किए गए काम और सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर है।

पिता जेल में, बेटा राष्ट्रपति बनने की रेस में

45 साल के फ्लावियो बोल्सोनारो इस चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि ब्राजील के बोल्सोनारो परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे रियो डी जेनेरियो से सीनेटर हैं।

उनके पिता जायर बोल्सोनारो जेल में होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में जायर ने अपने बेटे फ्लावियो को 2026 के चुनाव में आगे किया।

फ्लावियो 2002 से राजनीति में हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए यह उनका पहला चुनाव है। उन्होंने पिता की कट्टर दक्षिणपंथी छवि को आगे बढ़ाते हुए अपराध पर सख्त कार्रवाई, टैक्स में कटौती और कारोबार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों को अपने अभियान का हिस्सा बनाया है।



ब्राजील के राष्ट्रपति और वर्कर्स पार्टी के उम्मीदवार लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा 4 अक्टूबर 2026 को साओ पाउलो में।

ब्राजील में आम जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट करती है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलने जरूरी हैं। पहले दौर में फ्लावियो बोल्सोनारो को करीब 47% वोट मिले, जबकि लूला को करीब 45% वोट मिले।

प्रति मिनट 32000 फीट की रफ्तार से नीचे आ रहा था फ्लाईदुबई का प्लेन

बोइंग के डिजाइन ने कैसे टाली तबाही?

वाशिंगटन, एजेंसी

फ्लाईदुबई के विमान में बीच हवा में हुए जानलेवा हमले के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। शुरुआती रिपोर्टों में दो पायलटों के बीच कॉकपिट में हुई खूनी भिड़ंत, यात्रियों और ऑफ-ड्यूटी क्रू द्वारा विमान को संभालने की बहादुरी पर चर्चा रही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बोइंग 737 मैक्स विमान के मजबूत डिजाइन ने भी सभी अनुमानों को पीछे छोड़ दिया।

हवा में लगभग सीधी गोता लगाने के बावजूद विमान 170 से अधिक यात्रियों और चालक दल के साथ सऊदी अरब में सुरक्षित उतर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भी बोइंग के इस मजबूत डिजाइन की तारीफ की है।

को-पायलट ने मुख्य पायलट मच्छर पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद विमान खतरनाक



तरीके से पहले नीचे गोता लगाने लगा, फिर अचानक ऊपर चढ़ा और दोबारा तेजी से नीचे गिरने लगा।

फ्लाइटराडार24 के आंकड़ों के मुताबिक, एक समय विमान 32,000 फीट प्रति मिनट की भयानक रफ्तार से नीचे गिर रहा था। इस दौरान यात्रियों को लड़ाकू विमान चालकों और अंतरिक्ष यात्रियों जैसे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का सामना करना पड़ा।

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मुख्य पायलट कैप्टन स्मित मच्छर ने अंदर से कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जो केवल अंदर से ही खोला जा सकता था।

निगरानी : 200 लोग क्वॉरेंटाइन, प्लेग रिसर्च लैब में वायरस सैंपल वाली टेस्ट ट्यूब टूटी थी

रूस में अज्ञात वायरस से लैब कर्मचारी की मौत

मॉस्को, एजेंसी

रूस में 28 साल की महिला कर्मचारी की मौत के बाद उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। महिला साइबेरिया के एक एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी।

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, 25 सितंबर को लैब में काम करते समय उससे जीवित जैविक नमूनों वाली एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी।

29 सितंबर को तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। इलाज के दौरान 1 अक्टूबर की रात उसकी मौत हो गई।

महिला की मौत के बाद सवाल उठ रहा है कि उसे आखिर कौन सा संक्रमण हुआ था। उसे गंभीर



निमोनिया था, लेकिन बीमारी की वजह पता नहीं चल सकी। इसके बाद अधिकारियों ने इमरजेंसी मीटिंग की।

फिलहाल इसे अज्ञात कारणों वाला निमोनिया माना जा रहा है। निमोनिया वायरस और बैक्टीरिया दोनों से हो सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में फंगस या दूसरे कारण भी हो सकते हैं।

लैब के पास मौजूद एक एल्युमिनियम फैक्ट्री ने कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनने को कहा है। फैक्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद इलाके में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं।

रूस के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी गेन्नादी ओनिशेंको ने कहा कि फिलहाल यह बीमारी प्लेग लगने की संभावना कम है। उनका कहना है कि अगर प्लेग की पुष्टि भी होती है, तो इसके बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा नहीं है।

टेस्ट ट्यूब में क्या था, अभी पता नहीं

टेस्ट ट्यूब में किस तरह का जैविक नमूना था, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में इसे प्लेग से जुड़े नमूने से जोड़ा गया है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

वहीं, रूस की स्वास्थ्य एजेंसी रोस्पोट्रेबनादजोर ने लैब में किसी टेस्ट ट्यूब के टूटने से साफ इनकार किया है। एजेंसी ने कहा कि महिला के सैंपल में उसके लैब के काम से जुड़े सूक्ष्मजीव नहीं मिले।



28 साल की लैब टेक्नीशियन का नाम दर्या शिपिलोवा है। फोटो- सोशल मीडिया

पाकिस्तान में फिर बनी टकराव की स्थिति

सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थक

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। अपने नेता इमरान खान की रिहाई के लिए उनके हजारों समर्थकों ने रविवार को राजधानी इस्लामाबाद की ओर कूच कर दिया है। दरअसल, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह नाकाम रही, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। इमरान खान की पार्टी के सरकार वाले प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत जिले से विशाल मार्च शुरू हुआ। हजारों समर्थक ट्रकों, बसों और कारों के लंबे काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आयोजकों ने इस्लामाबाद पहुंचने से पहले रास्ते में रात के ठहराव की योजना बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा के



मुख्यमंत्री और इमरान खान के कट्टर समर्थक सोहेल अफरीदी इस मार्च की अगुवाई कर रहे हैं। इमरान खान की बड़ी तस्वीर वाले एक कंटेनर ट्रक से बोलते हुए अफरीदी ने भरोसा जताया कि आंदोलन अपनी मांगों को राजधानी के केंद्र तक पहुंचाने में सफल रहेगा। प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों और प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। राजधानी के सभी प्रवेश द्वारों और शहर के भीतर कई प्रमुख चौराहों पर शिपिंग कंटेनर रखकर भारी बैरिकेडिंग की गई है, जिससे पूरा शहर छावनी में तब्दील नजर आ रहा है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676